

वीकली वन लाइनर्स 27 जुलाई से 1 अगस्त, 2026

ग्लोबल टाइगर डे 2026 रिपोर्ट: भारत में बाघों की आबादी बढ़कर 3,682 हुई; टाइगर रिजर्व बढ़कर 58 हुए

ग्लोबल टाइगर डे 2026 के मौके पर, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने पिछले 12 सालों में वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन में भारत की शानदार तरक्की के बारे में बताया। नई दिल्ली में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) द्वारा आयोजित सेलिब्रेशन को संबोधित करते हुए, मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में टाइगर की आबादी बढ़कर 3,682 हो गई है, जबकि टाइगर रिजर्व की संख्या 58 हो गई है।

इस इवेंट में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह, सीनियर सरकारी अधिकारी, वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट, फ्रंटलाइन फॉरेस्ट कर्मचारी, स्टूडेंट्स और वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन के लिए कमिटेड दूसरे स्टेकहोल्डर्स शामिल हुए।

बाघ संरक्षण में भारत की बढ़ती सफलता

अपने भाषण के दौरान, श्री भूपेंद्र यादव ने इस बात पर ज़ोर दिया कि वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन का मतलब सिर्फ जानवरों की रक्षा करना नहीं है, बल्कि इसमें लोगों और प्रकृति के बीच एक अच्छा रिश्ता बनाना भी शामिल है।

उन्होंने कहा कि पिछले 12 सालों में भारत में न सिर्फ बाघों और टाइगर रिजर्व की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है, बल्कि इन चीज़ों में भी बढ़ोतरी हुई है:

- हाथी अभयारण्य
- राष्ट्रीय उद्यान
- वन्यजीव अभयारण्य
- संरक्षित क्षेत्र
- सामुदायिक रिजर्व
- वेटलैंड्स

मंत्री ने इन उपलब्धियों का श्रेय लगातार संरक्षण प्रयासों, साइंटिफिक मैनेजमेंट और बढ़ती हुई पब्लिक भागीदारी को दिया।

NTCA ने इंटीग्रेटेड इको-टूरिज्म वेबपेज लॉन्च किया

NTCA इको-टूरिज्म वेबपेज का लॉन्च था, जो एक इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो पूरे भारत के सभी टाइगर रिजर्व के बारे में असली जानकारी देता है।

प्रमुख विशेषताएँ

- ऑफिशियल टाइगर रिजर्व वेबसाइट के डायरेक्ट लिंक।
- ऑनलाइन सफारी बुकिंग की जानकारी।
- रहने की बुकिंग की सुविधा।
- ज़िम्मेदार और सस्टेनेबल इको-टूरिज्म को बढ़ावा देना।
- विज़िटर्स के लिए वेरिफाइड जानकारी तक आसान एक्सेस।

इस पहल का मकसद इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी पक्का करते हुए नेचर-बेस्ड टूरिज्म को बढ़ावा देना है।

संरक्षण में ज्ञान साझा करने का महत्व

मंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन सिर्फ साइंटिफिक डेटा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पारंपरिक ज्ञान, फ़ील्ड अनुभव और फ़ॉरेस्ट अधिकारियों का समर्पण भी शामिल है।

उन्होंने वाइल्डलाइफ अधिकारियों और कंजर्वेशनिस्ट को अपने अनुभव डॉक्यूमेंट करने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि प्रैक्टिकल जानकारी भविष्य की कंजर्वेशन पॉलिसी और मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी में मदद कर सके।

क्षमता निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

श्री यादव ने दुनिया के सबसे अच्छे तरीकों को अपनाकर फॉरेस्ट अधिकारियों के लिए लगातार कैपेसिटी बिल्डिंग के महत्व पर ज़ोर दिया। दुनिया भर में बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल सहयोग, ज्ञान के आदान-प्रदान और साइंटिफिक सहयोग को बढ़ावा देने में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) की बढ़ती भूमिका पर भी ज़ोर दिया।

एनटीसीए पुरस्कार प्रदान किए गए

वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन में शानदार योगदान को पहचानने के लिए, NTCA अवॉर्ड्स दिए गए:

- वन्यजीव अधिकारी
- वन अधिकारियों
- संरक्षण पेशेवर
- अग्रिम पंक्ति के वन कर्मियों

इन अवॉर्ड्स में देश भर में टाइगर कंजर्वेशन और प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट में बहुत अच्छे काम को पहचान दी गई।

राष्ट्रव्यापी बाघ संरक्षण जागरूकता अभियान

ग्लोबल टाइगर डे सेलिब्रेशन के हिस्से के तौर पर, NTCA ने मिनिस्ट्री के एनवायरनमेंट एजुकेशन प्रोग्राम के तहत इको-क्लब के ज़रिए पूरे देश में अवेयरनेस कैम्पेन चलाया।

इस पर खास ज़ोर दिया गया:

- टाइगर रिजर्व के पास स्थित स्कूल
- छात्र भागीदारी
- वन्यजीव जागरूकता गतिविधियाँ
- चित्रकला प्रतियोगिताएं
- स्केचिंग प्रतियोगिताएं
- नारा-लेखन प्रतियोगिताएं
- “बाघ बचाओ” थीम पर आधारित मास्क बनाने की प्रतियोगिता

जारी किए गए प्रकाशन

इस इवेंट के दौरान वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन और साइंटिफिक मैनेजमेंट पर फोकस करने वाले पाँच ज़रूरी पब्लिकेशन रिलीज़ किए गए:

1. स्ट्राइप्स – NTCA आउटरीच जर्नल (जुलाई 2026 एडिशन)
2. 24 टाइगर रिजर्व की सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट
3. भारत में बाघों वाले इलाकों में स्लॉथ भालुओं के लिए रहने की जगह की उपयुक्तता का आकलन

4. **टाइगर्स ऑफ़ द वर्ल्ड** (IBCA और ग्लोबल टाइगर फ़ोरम द्वारा प्रकाशित)

5. चंद्र प्रकाश गोयल और सत्य प्रकाश यादव की **द रहमान खेड़ा टाइगर**

इन पब्लिकेशन का मकसद वाइल्डलाइफ़ कंज़र्वेशन के बारे में रिसर्च, पॉलिसी-मेकिंग और पब्लिक अवेयरनेस को मज़बूत करना है।

पृष्ठभूमि: वैश्विक बाघ दिवस

दुनिया भर में बाघों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल **29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है।**

इस दिन की स्थापना **सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट (2010) के दौरान की गई थी**, जहां **13 टाइगर रेंज देशों ने ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम (GTRP)** लॉन्च किया था।

समिट में बड़े **TX2 गोल को भी पेश किया गया**, जिसका मकसद 2022 तक दुनिया भर में जंगली बाघों की आबादी को दोगुना करना है।

बाघों के लिए खतरे

संरक्षण में सफलता के बावजूद, बाघों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है:

- अवैध शिकार
- अवैध वन्यजीव व्यापार
- प्राकृतवास नुकसान
- आवास विखंडन
- मानव-वन्यजीव संघर्ष
- जलवायु परिवर्तन

आज, जंगली बाघ **अपनी ऐतिहासिक सीमा के 8% से भी कम क्षेत्र पर कब्जा करते हैं**, जबकि तीन उप-प्रजातियां— **बाली टाइगर, जावन टाइगर, और कैस्पियन टाइगर**—विलुप्त हो गई हैं।

कैबिनेट ने फ्लोटिंग सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (PM-SSY) को मंजूरी दी

माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (PM-SSY) को मंजूरी दे दी है, जिसका कुल खर्च ₹5,070 करोड़ है। इस पहल की घोषणा 31 जुलाई 2026 को की गई थी और इसमें भारत में एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (ESS) के साथ इंटीग्रेटेड 5,000 MW के फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक (FSPV) प्रोजेक्ट लगाने का लक्ष्य है। PM-SSY का मकसद जलाशयों और अंदरूनी पानी की जगहों का इस्तेमाल करके सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना है, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता बढ़ेगी, ग्रिड की स्थिरता में सुधार होगा और कार्बन एमिशन कम होगा और आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के विज़न में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (PM-SSY) क्या है?

प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (PM-SSY) एक बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी पहल है जिसका मकसद पूरे भारत में अलग-अलग पानी की जगहों, जैसे तालाबों, झीलों और बांधों में फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक (FSPV) प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देना है।

इस पहल में भरोसेमंद बिजली देने और इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में स्थिरता बनाए रखने के लिए एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (ESS) के साथ फ्लोटिंग सोलर पावर स्टेशनों का इस्तेमाल किया जाता है। यह प्रोग्राम भारत में फ्लोटिंग सोलर टेक्नोलॉजी के लिए खास तौर पर बनाए गए सबसे बड़े प्रोग्राम में से एक है।

यह प्रोजेक्ट FY 2026-27 से FY 2030-31 तक चलेगा, और फाइनेंशियल सपोर्ट FY 2032-33 तक दिया जाएगा।

सोलर एनर्जी के लिए पीएम स्कीम की खास बातें

PM स्कीम में भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई नए इनिशिएटिव हैं।

मुख्य बातें नीचे दी गई हैं,

- इस स्कीम का कुल बजट ₹5,070 करोड़ है।
- कैपेसिटी का टारगेट 5,000 MW फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स का है।
- इस संबंध में, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की कम से कम 10,000 MWh कैपेसिटी (दो घंटे) होनी चाहिए।
- यह स्कीम FY 2026-27 से FY 2030-31 तक लागू होगी।
- फाइनेंशियल मदद का डिस्ट्रीब्यूशन FY 2032-33 तक होगा।
- सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस (CFA) का प्रोविज़न ₹1 करोड़ प्रति MW है।
- फ्रीज़िबिलिटी स्टडीज़ करने में मदद ₹50 लाख तक है।
- यह स्कीम पूरे भारत में लागू की जाएगी।

इस स्कीम से भारत की फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी काफी बढ़ने की उम्मीद है, साथ ही पारंपरिक एनर्जी सोर्स पर निर्भरता भी कम होगी।

फ्लोटिंग सोलर क्यों ज़रूरी है?

फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉलेशन आम सोलर प्लांट से अलग होते हैं जो ज़मीन पर लगे होते हैं, क्योंकि वे पानी की जगहों पर होते हैं।

इस तरह की टेक्नोलॉजी के कुछ फायदे हैं जैसे,

- कीमती ज़मीन बचती है।
 - मौजूदा प्राकृतिक पानी की जगहों का इस्तेमाल करता है।
 - इवैपोरेशन को रोकने में मदद करता है।
 - पानी के नेचुरल कूलिंग इफ़ेक्ट का इस्तेमाल करता है जिससे सोलर इक्विपमेंट की एफिशिएंसी बेहतर होती है।
 - इंफ्रास्ट्रक्चर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है।
- फ्लोटिंग सोलर एनर्जी सॉल्यूशन दुनिया भर में पॉपुलर हो रहे हैं, क्योंकि खेती की ज़मीन या शहरी इलाकों को नुकसान पहुँचाए बिना एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के तरीके मौजूद हैं।

एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (ESS): एक मुख्य हिस्सा

एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (ESS) एक ज़रूरी हिस्सा है।

PM-SSY के मुख्य हिस्सों में से एक यह है कि हर फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट को ESS का इस्तेमाल करना होगा।

प्लान के अनुसार, हर प्रोजेक्ट में कम से कम दो घंटे की स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए, जिससे कुल 10,000 MWh स्टोरेज कैपेसिटी होगी।

एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का महत्व यह है कि,

- वे पीक सन आवर्स के दौरान बनी एक्स्ट्रा बिजली को स्टोर कर सकते हैं।
 - वे ऐसे समय में एनर्जी देने में मदद करते हैं जब सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन कम होता है।
 - वे ग्रिड को स्थिर करने में मदद करते हैं।
 - वे नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में रिन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ावा देते हैं।
 - वे बिजली सप्लाई में उतार-चढ़ाव को खत्म करने में मदद करते हैं।
- सोलर और बैटरी पावर का कॉम्बिनेशन क्लीन एनर्जी को और भी भरोसेमंद बनाता है।

पीएम-एसएसवाई के तहत वित्तीय सहायता

प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में आसानी हो और प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंशियल रिस्क कम से कम हो, इसके लिए सरकार फाइनेंशियल मदद के ज़रिए सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस (CFA) के रूप में काफी मदद दे रही है।

कमीशनिंग सहायता

इस स्कीम के लिए एलिजिबल फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को प्रोजेक्ट के सक्सेसफुली चालू होने के बाद हर MW के लिए ₹1 करोड़ मिलेंगे।

व्यवहार्यता अध्ययन सहायता

प्रोजेक्ट डेवलपर्स को ये मिलेगा,

हर प्रोजेक्ट के लिए ₹50 लाख तक।

यह मदद, इन कामों को करने के लिए मान्य है,

- बैथिमेट्रिक अध्ययन।
- हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण।
- EC अध्ययन।
- टेक्निकल सर्वे।
- प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ज़रूरी दूसरी तैयारी की पढ़ाई।

इन उपायों का मकसद प्रोजेक्ट के रिस्क को कम करना और प्रोजेक्ट को जल्दी पूरा करना है।

भारत की अस्थिर सौर क्षमताएँ

यह मंजूरी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोलर एनर्जी (NISE) के असेसमेंट पर आधारित है।

आकलन के अनुसार,

- भारत के लिए अनुमानित फ्लोटिंग सोलर पोटेन्शियल लगभग 102.18 GWp है।
- असेसमेंट में जलाशय और अंदरूनी पानी की चीज़ें शामिल हैं जो देश के लिए सही हैं।

अभी, भारत की स्थापित फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी लगभग 700 MW मानी जाती है।

PM-SSY के साथ, भारत का लक्ष्य फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी को और 5,000 MW तक बढ़ाना है।

कैबिनेट ने ₹36,441 करोड़ के खर्च के साथ खेलो इंडिया स्कीम को नया रूप देने और ANSF सपोर्ट बढ़ाने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 2026-27 से 2030-31 तक के समय के लिए नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (NSF) को ज्यादा मदद के साथ-साथ रीस्ट्रक्चर्ड खेलो इंडिया स्कीम को मंजूरी दे दी है। ₹36,441 करोड़ के कुल फ़ाइनैशियल खर्च वाली इस रीस्ट्रक्चर्ड स्कीम को आज़ादी के बाद से स्पोर्ट्स डेवलपमेंट में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होने का गौरव हासिल है। इस नई स्कीम का मकसद एथलीटों के लिए ज़मीनी स्तर से लेकर ओलंपिक गेम्स तक का एक आसान रास्ता बनाना है, साथ ही फिटनेस, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी-बेस्ड गवर्नेंस और सबको साथ लेकर चलने वाले स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है।

नया खेलो इंडिया प्लान क्या है?

नया खेलो इंडिया प्लान भारत सरकार का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसे सभी लेवल के स्पोर्ट्स टैलेंट को पहचानने, ट्रेनिंग देने और सपोर्ट करने के लिए शुरू किया गया है।

इस स्कीम का मकसद यह पक्का करना है कि कोई भी उभरता हुआ खिलाड़ी सही सुविधाओं तक कम पहुंच और पैसे की कमी की वजह से मौकों से दूर न रहे।

खेलो भारत नीति 2025 और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार, इस प्लान में स्पोर्ट्स को एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, फिटनेस और हाई-परफॉर्मेंस ट्रेनिंग के साथ मिलाया गया है।

इसके साथ ही भारत सरकार भविष्य के लिए प्लान लागू करना चाहती है, जिसमें कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की तैयारी और ओलंपिक और पैरालिंपिक गेम्स होस्ट करने का इरादा शामिल है।

खेलो इंडिया योजना की मुख्य बातें

खेलो इंडिया स्कीम की खास बातें ये हैं :

बजट: ₹ 36,441 करोड़ (खेलो इंडिया+ANSF) ने 2026-27 से 2030-31 तक के लिए प्लान बनाया है।

- यह आज़ादी के बाद खेलों में किया गया सबसे बड़ा निवेश है।
- खेलो इंडिया में पहले किए गए निवेश से लगभग 8 गुना ज्यादा है।
- इस प्लान में एथलीटों को डेवलप करने और ट्रेन करने के कई तरीके बताए गए हैं।
- इमर्जिंग खेलो इंडिया एथलीट्स (E-KIA) की स्थापना।
- खेलो इंडिया फीडर स्कूल (KIFS) की शुरुआत।
- खेलो इंडिया उत्कृष्ट की स्थापना विद्यालय (केआईयूवी)।
- नेशनल कोच एक्जिटेशन बोर्ड बनाना।
- फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत।
- वन-स्टॉप डिजिटल स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म का डेवलपमेंट।
- नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (ANSFs) को दी जाने वाली मदद को और मज़बूत किया गया है।

भारत में खेल सुविधाओं को मजबूत करना

यह प्रोजेक्ट स्पोर्ट्स सेंटर्स के एक नेशनल चैनल को चौड़ा करेगा और जोड़ेगा।

सुविधाओं में शामिल हैं,

- राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई)
- खेलो इंडिया उत्कृष्टता केंद्र (केआईसीओई)
- भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी)
- खेलो इंडिया मान्यता प्राप्त अकादमियाँ (KIAAs)
- खेलो इंडिया केंद्र (केआईसी)
- सशस्त्र बलों की युवा खेल कंपनियाँ (YSCs)

सभी देंगे

- पेशेवर कोचिंग
- आधुनिक बुनियादी ढांचा
- खेल विज्ञान सेवाएँ
- प्रदर्शन मूल्यांकन
- पोषण और पुनर्प्राप्ति सहायता

राष्ट्रीय कोच मान्यता प्राधिकरण (एनसीएए)

कोचों के महत्व को समझते हुए, सरकार एक नेशनल कोच एकेडिटेेशन अथॉरिटी (NCAA) बनाने की योजना बना रही है।

उद्देश्य हैं,

- कोचिंग सर्टिफिकेशन की कालिटी को मेनस्ट्रीम में लाने के लिए,
- कोचिंग के स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने के लिए,
- कोचों को ट्रेनिंग देने के तरीकों में सुधार करना, और
- सपोर्ट स्टाफ की क्षमता बढ़ाना।

इसलिए, उम्मीद है कि बोर्ड पूरे भारत में कोचिंग को ज़्यादा असरदार और प्रोफेशनल बनाएगा।

कैबिनेट ने ₹84,084 करोड़ के खर्च के साथ 'समुद्र मंथन' नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम को मंजूरी दी

माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 'समुद्र मंथन' नाम की नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम को पास किया। इसमें ₹84,084 करोड़ का निवेश होगा और इसे FY 2030-31 तक लागू किया जाएगा। 31 जुलाई 2026 को इसकी घोषणा की गई थी। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की इस सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मकसद एडवांस्ड एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और साइंटिफिक रिसर्च का इस्तेमाल करके भारत के बड़े ऑफशोर तेल और गैस रिसोर्स को बढ़ाना है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाने, इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने और विकसित भारत के बड़े मकसद के तहत दुनिया भर में मुकाबला करने वाला ऑफशोर एनर्जी इकोसिस्टम बनाने के विजन के मुताबिक है।

समुद्र मंथन योजना क्या है?

समुद्र मंथन स्कीम, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री की शुरू की गई एक बड़ी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका मकसद देश के सभी समुद्री इलाकों में ऑफशोर तेल और गैस की खोज को बढ़ावा देना है। इस स्कीम की मदद से, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से प्रेरित है, जिन्होंने जनवरी 2025 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने भाषण में इसके बारे में बात की थी, ऑफशोर हाइड्रोकार्बन में भारत की क्षमता का इस्तेमाल टारगेटेड पब्लिक फंडिंग, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और हाई-लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए किया जाएगा। यह तरीका भविष्य में भारत को एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ाने में भी मदद करेगा।

समुद्र मंथन योजना की मुख्य बातें

समुद्र मंथन स्कीम में ऑफशोर एक्सप्लोरेशन में एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन के सभी पहलू शामिल हैं।

सरकार ने इस स्कीम की सफलता के लिए ₹84,084 करोड़ अलग रखे हैं। यह बड़ी रकम इसे देश में ऑफशोर एक्सप्लोरेशन में सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट में से एक बनाती है।

यह स्कीम फिस्कल ईयर 2030-31 तक चलेगी, जिससे एक्सप्लोरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में ठीक-ठाक मात्रा में इन्वेस्टमेंट पक्का होगा।

इस प्रोग्राम का मुख्य मकसद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और तेज़ ड्रिलिंग ऑपरेशन का इस्तेमाल करके भारत के ऑफशोर एनर्जी रिसोर्स की क्षमता का इस्तेमाल करना है।

कार्यक्रम के मुख्य घटक

समुद्र मंथन में भारत की ऑफशोर एक्सप्लोरेशन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कई स्ट्रेटेजिक पहल शामिल हैं।

- बड़े पैमाने पर सिस्मिक डेटा इकट्ठा करना: यह प्रोग्राम संभावित हाइड्रोकार्बन डिपॉज़िट का पता लगाने के लिए सिस्मिक डेटा को बड़े पैमाने पर इकट्ठा करने, प्रोसेस करने और समझने की सुविधा देता है।
- गहरे पानी में खोज: इस प्रोग्राम को गहरे पानी और बहुत गहरे पानी वाले इलाकों में खोजी ड्रिलिंग के काम को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है, माना जाता है कि इनमें काफ़ी अनछुए एनर्जी रिज़र्व हैं।
- फ्रंटियर बेसिन में एक्सप्लोरेशन के लिए साइंटिफिक ड्रिलिंग: बेहतर जियोलॉजिकल जानकारी और भविष्य में एक्सप्लोरेशन के लिए फ्रंटियर ऑफशोर बेसिन में खास साइंटिफिक ड्रिलिंग ऑपरेशन का इस्तेमाल किया जाएगा।
- ऑफशोर प्रोडक्शन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर: इस प्रोग्राम में हाइड्रोकार्बन का असरदार एक्सट्रैक्शन और ट्रांसपोर्टेशन पक्का करने के लिए कॉमन ऑफशोर प्रोडक्शन और इवैक्युएशन फैसिलिटी बनाना भी शामिल है।
- ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री प्रोडक्शन एंड सर्विसेज़ ज़ोन: मेक इन इंडिया कैपेन के तहत ऑफशोर इक्विपमेंट के घरेलू प्रोडक्शन, इंजीनियरिंग सपोर्ट सर्विस और दूसरी संबंधित एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने के लिए एक मैनुफैक्चरिंग और सर्विस सेंटर बनाया जाएगा।

प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण

समुद्र मंथन का ज़ोर नई टेक्नोलॉजी अपनाने और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को बढ़ाने पर है।

प्रोग्राम में ये चीज़ें दी गई हैं,

- डिजिटल कार्यक्रमों का ई-प्रबंधन
- प्रौद्योगिकी को अपनाना
- क्षमता निर्माण
- हितधारकों की भागीदारी
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आउटरीच गतिविधियाँ

इसका मकसद एक ऐसा इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम बनाना है जो ऑफशोर एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स को अच्छे से और सस्टेनेबल तरीके से पूरा कर सके।

इस पहल के अपेक्षित लाभ

अधिकारियों को समुद्र मंथन से काफी आर्थिक और स्ट्रेटेजिक फायदे होने की उम्मीद है।

अतिरिक्त ऊर्जा भंडार की खोज

इस पहल से 600 MMTOE से ज्यादा तेल की खोज होने की संभावना है, जिससे भारत में हाइड्रोकार्बन रिज़र्व में काफी बढ़ोतरी होगी।

ऊर्जा सुरक्षा की उन्नति

देश में कच्चे तेल और गैस का प्रोडक्शन बढ़ने से एनर्जी के विदेशी स्रोत पर निर्भरता कम होगी, जिससे लंबे समय में एनर्जी सिक्योरिटी में मदद मिलेगी।

नौकरियों का सृजन

ऑफशोर एक्सप्लोरेशन के बढ़ने से एक्सप्लोरेशन, इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के फील्ड में नौकरी के कई मौके मिलेंगे।

'मेक इन इंडिया' पहल के लिए समर्थन

एक कोहेसिव मैनुफैक्चरिंग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने से ऑफशोर प्रोडक्शन के लिए लोकल टेक्नोलॉजी और इन्फ्रैस्ट्रक्चर का डेवलपमेंट शुरू होगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत की सफलता पक्की होगी।

निवेश में वृद्धि

उम्मीद है कि समुद्र मंथन से एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट होगा, जिससे इंडस्ट्री के डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा।

कैबिनेट ने ₹3.15 लाख करोड़ के खर्च के साथ 2030-31 तक पीएम-किसान स्कीम को जारी रखने की मंजूरी दी

यूनिफ़ाईड कैबिनेट ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) स्कीम को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। यह किसानों की भलाई और गांव के विकास में मदद करने के सरकार के वादे को पक्का करता है। मंजूरी के मुताबिक, इस स्कीम पर ₹3.15 लाख करोड़ खर्च होंगे और यह योग्य ज़मीन वाले परिवारों को हर साल ₹6,000 देती रहेगी। इसे साल 2019 में लागू किया गया था, PM-KISAN भारत की सबसे बड़ी इनकम सपोर्ट स्कीम बन गई, जिससे किसानों को खेती के काम करने में मदद मिली, इनफॉर्मल लोन पर उनकी निर्भरता कम हुई, और उन्हें ट्रांसपेरेंट और टेक्नोलॉजी-बेस्ड तरीके से गुज़ारा करने में मदद मिली।

पीएम-किसान योजना क्या है?

PM-KISAN स्कीम भारत सरकार ने फरवरी 2019 में किसानों को इनकम सपोर्ट देने के लिए लागू की थी।

इस प्रोग्राम के तहत किसानों को सीधे उनके बैंक अकाउंट में ₹6,000 मिलेंगे।

यह प्रोग्राम फंड डिस्बर्सल प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट रखने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाता है।

केंद्र ने 2030-31 तक PM-KISAN को जारी रखने की मंजूरी दी

केंद्रीय कैबिनेट ने PM-KISAN स्कीम को पांच साल (2026 से 2030 तक) के लिए बढ़ाने का फैसला किया है।

इस स्कीम के लिए इस समय तक कुल ₹3.15 लाख करोड़ का फाइनेंशियल प्रोविज़न है, ताकि योग्य किसानों को बिना किसी रुकावट के इनकम में मदद मिल सके।

यह पहल किसानों की इनकम, खेती में इन्वेस्टमेंट और पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मामलों में सरकार की गंभीरता को दिखाती है।

पीएम-किसान योजना से मुख्य बातें

अपनी शुरुआत से ही, इस प्रोग्राम ने कई ज़रूरी बेंचमार्क पूरे किए हैं। वित्तीय सहायता

- यह स्कीम योग्य किसानों को सालाना 6000 रुपये की मदद देती है।
- फंड तीन तरह से सीधे बैंक ट्रांसफर के ज़रिए भेजे जाते हैं।

कुल हस्तांतरित राशि

- 22 हिस्सों में किसानों के बैंक अकाउंट में 447000 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम जमा की जा चुकी है।

सबसे हालिया संवितरण

- 23वीं किस्त से 9.49 करोड़ किसानों को मदद मिली।
- इस किस्त में दी गई रकम 18984 करोड़ रुपये थी।

COVID-19 के दौरान सहायता

- महामारी के समय में किसानों को 171000 करोड़ रुपये दिए गए और खेती में मदद की गई।

महिला किसानों को सहायता

- करोड़ रुपये मिले, जिसमें से लगभग हर चार में से एक फायदा उठाने वाली महिला किसान थी।

किसानों को समर्थन देने में पीएम-किसान की भूमिका

PM-KISAN से मिलने वाली फाइनेंशियल मदद से किसान सही समय पर खेती के सामान में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस सालाना मदद से खेतों की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं।

सालाना मिलने वाली रकम से किसान खरीद सकते हैं,

- गुणवत्ता वाले बीज
- उर्वरक
- सिंचाई उपकरण
- कृषि मशीनरी
- खेती के लिए अन्य ज़रूरी इनपुट।

पहले से पता फाइनेंशियल मदद देकर, यह स्कीम किसानों को क्रेडिट के इनफॉर्मल स्रोत पर कम डिपेंडेंट बनाती है और गांव के परिवारों को फाइनेंशियली स्टेबल करती है।

स्वतंत्र मूल्यांकन की मुख्य बातें

इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन में PM-KISAN स्कीम से हुए पॉज़िटिव असर को माना गया है।

नीति आयोग के तहत डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस (DMEO) द्वारा किए गए इवैल्यूएशन के अनुसार, यह पाया गया कि,

- 92% से ज्यादा बेनिफिशियरी ने इस रकम का इस्तेमाल खेती के कामों और खेती के कामों में इन्वेस्टमेंट के लिए किया।
- लगभग 85% लोगों ने कहा कि उनकी खेती से होने वाली इनकम बढ़ी है और इनफॉर्मल उधार पर उनकी डिपेंडेंस कम हुई है।

नतीजों से पता चलता है कि PM-KISAN खेती में फायदेमंद निवेश के मौके बनाने में फायदेमंद रहा है।

कृषि विकास में योगदान

2020-21 से 2025-26 तक भारत के कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार हुए। इस काल में,

- कुल खेती का एरिया लगभग 9.65% बढ़ गया।
- खेती में प्रोडक्टिविटी लगभग 10.53% बढ़ी।
- कुल अनाज उत्पादन में लगभग 21.18% की वृद्धि हुई।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, यह PM-KISAN समेत किसानों के लिए अलग-अलग मदद के तरीकों और आम तौर पर खेती की बेहतरी की वजह से मुमकिन हुआ है।

डिजिटल इंडिया और पारदर्शी डिलीवरी

डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट PM-KISAN प्रोग्राम के ज़रिए दिखाया गया है।

आधार पर आधारित डिजिटल वेरिफिकेशन जैसी टेक्नोलॉजी की मदद से, बिना किसी बिचौलिए के सीधे बेनिफिशियरी तक फाइनेंशियल मदद अच्छे से पहुंचाई जा सकती है।

इस तरह, डिजिटल तरीके से ट्रांसपेरेंसी बेहतर हुई है, रिसोर्स का लीकेज कम हुआ है, पेमेंट जल्दी हुआ है, और किसानों और सरकार के बीच भरोसा बढ़ा है।

सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल UNESCO की विश्व धरोहर सूची में शामिल

उत्तर प्रदेश में मौजूद एक पुरानी बौद्ध जगह, सारनाथ, 25 जुलाई, 2026 को साउथ कोरिया के बुसान में हुए वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी के 48वें सेशन में UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुई। इसके साथ ही सारनाथ भारत की 45वीं UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई है, साथ ही इतिहास, धर्म और संस्कृति के मामले में भी इसकी अहमियत पर ज़ोर दिया गया है। यह जगह गौतम बुद्ध ने ज्ञान पाने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था, इस जगह के तौर पर इसे बड़े पैमाने पर जाना जाता है। सारनाथ 2500 सालों से शांति, ज्ञान और आध्यात्मिकता की निशानी रहा है। यह लिखावट भारत की समृद्ध विरासत में इज़ाफ़ा करती है और बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक को बचाने की दुनिया भर की कोशिशों को और भी अहमियत देती है।

सारनाथ को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया

वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी ने कोरिया गणराज्य के बुसान में हुई अपनी 48वीं मीटिंग में प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गनाइज़ेशन की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने का फैसला किया।

इस प्रकार,

- अब भारत में 45 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं।
- सारनाथ आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू वाली जगहों की लिस्ट में है।
- यह शिलालेख दुनिया के इतिहास, संस्कृति और धर्म में सारनाथ के योगदान को स्वीकार करता है।

UNESCO का यह फैसला पूरी इंसानियत की सांस्कृतिक विरासत की जगहों को बचाने की उसकी कोशिशों को दिखाता है।

सारनाथ को क्या खास बनाता है?

सारनाथ का महत्व बौद्ध धर्म के इतिहास में इसके खास स्थान में है। छठी सदी में बोधगया में ज्ञान पाने के बाद अपना पहला उपदेश (धम्मचक्कप्पवत्तन सुत्त) दिया था।

इस इवेंट का महत्व नीचे दी गई बातों में है,

- बौद्ध धर्म के प्रचार की शुरुआत।
- बौद्ध मठ (संघ) की स्थापना।
- बौद्ध धर्म का आधार।

यही वजह है कि सारनाथ, लुम्बिनी, बोधगया और कुशीनगर के बाद चौथा सबसे पवित्र बौद्ध स्थान है।

सारनाथ के ऐतिहासिक स्मारक

सदियों के बदलाव में राजाओं, साधुओं और बौद्ध धर्म के मानने वालों ने सारनाथ शहर को बौद्ध धर्म की पढ़ाई का एक जाना-माना सेंटर बना दिया है।

शहर के महत्वपूर्ण स्मारकों में निम्नलिखित शामिल हैं,

धमेक स्तूप

धमेक स्तूप सारनाथ की सबसे मशहूर यादगार जगह है। यह बड़ा बेलनाकार स्तूप उस जगह पर बनाया गया था जहाँ कहा जाता है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसमें पत्थर पर बहुत अच्छी नक्काशी की गई है। यह हर साल हज़ारों लोगों को अपनी ओर खींचता है।

धर्मराजिका स्तूप

अभी खंडहर में पड़ा धर्मराजिका स्तूप बौद्ध धर्म के सबसे पुराने स्तूपों में से एक है और पारंपरिक रूप से सम्राट अशोक से जुड़ा रहा है, जिन्होंने बौद्ध धर्म को फैलाने में अहम भूमिका निभाई थी।

चौखंडी स्तूप

चौखंडी स्तूप उस घटना की याद दिलाता है जब बुद्ध ने अपना पहला उपदेश देने से पहले अपने पहले शिष्यों से मुलाकात की थी। यह बौद्ध धर्म के इतिहास में एक अहम घटना थी।

ये स्मारक उस जगह को दिखाते हैं जिसे डियर पार्क (मृगदाव) के नाम से जाना जाता है, वह जगह जहाँ बौद्ध धर्म ने एक वर्ल्ड धर्म के तौर पर अपनी यात्रा शुरू की थी।

यूनेस्को की मान्यता और उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य

UNESCO ने इन वजहों से सारनाथ को इस लिस्ट में शामिल होने लायक और खास माना है,

- सारनाथ का एक प्रमुख धर्म से संबंध।
- दो हज़ार साल से भी ज़्यादा समय से इसका महत्व लगातार बना हुआ है।
- बौद्ध धर्म का सम्मान करने वाली पुरानी और बड़ी कलाकृतियां मौजूद हैं।
- पूरे एशिया में दर्शन, शिक्षा और तीर्थयात्रा पर प्रभाव।
- भविष्य अच्छा है क्योंकि इस साइट पर UNESCO की पहचान से पूरा ध्यान और सुरक्षा मिलेगी।

सारनाथ के इंटरनेशनल महत्व के बारे में UNESCO का संदेश
शिलालेख मिलने के बाद, UNESCO इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ साउथ एशिया के डायरेक्टर टिम कर्टिस ने भारत को बधाई दी और बताया कि सारनाथ दो हजार सालों से कई बौद्ध भिक्षुओं को प्रेरणा देता रहा है। उन्होंने कहा कि सारनाथ के मंदिर, मठ और स्तूप दया, बुद्धिमत्ता, विश्वास और साझा मानवीय विरासत की निशानी हैं। UNESCO ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि इस जगह की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी अभी की और आने वाली पीढ़ियों की है।

राष्ट्रीय समाचार

- **भारत सरकार ने** भारत के एग्जामिनेशन सिस्टम का भरोसा मज़बूत करने के लिए **इंफोसिस** के को-फाउंडर **नंदन नीलेकणी** की अध्यक्षता में एक **हाई-पावर्ड एग्जाम रिफॉर्म टास्क फोर्स** बनाई है। यह **पैनल पेपर लीक रोकने**, **गलत तरीकों पर रोक लगाने**, **ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने**, **टेक्नोलॉजी-बेस्ड मॉनिटरिंग में सुधार करने**, **सिक््योरिटी सिस्टम को मज़बूत करने** और **एग्जाम मैनेजमेंट को मॉडर्न बनाने के लिए सुधारों की सिफारिश करेगा**। दूसरे सदस्यों में **डॉ. एस. सोमनाथ**, **तपन डेका**, **प्रो. वी. कामकोटि**, **अनीता करवाल** और **अमृत लाल मीणा** शामिल हैं। यह पहल **प्रपोज्ड पब्लिक एग्जामिनेशन (गलत तरीकों से बचाव) अमेंडमेंट बिल, 2026** से पहले की गई है, जिसमें एग्जाम में धोखाधड़ी के लिए कड़ी सज़ा की मांग की गई है।
- **यूनिवर्सिटी ऑफ़ लीड्स** और **IIT खड़गपुर** ने **रिसर्च, एजुकेशन, इनोवेशन और स्टूडेंट मोबिलिटी** में सहयोग को गहरा करने के लिए एक **स्ट्रेटिजिक मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (MoU)** पर साइन किए। यह **पार्टनरशिप फैकल्टी और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम**, **जॉइंट एकेडमिक पहल**, **एंटरप्रेन्योरशिप और इंडस्ट्री सहयोग** को बढ़ावा देती है। यह **इनोवेशन को प्रैक्टिकल सॉल्यूशन में बदलने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, स्टार्टअप सपोर्ट और रिसर्च कमर्शियलाइज़ेशन** पर भी फोकस करता है। यह **एग्रीमेंट इंडिया-UK एकेडमिक संबंधों को और मजबूत करता है, ग्लोबल टैलेंट डेवलपमेंट को बढ़ाता है, इंटरनेशनल रिसर्च के मौकों को बढ़ाता है, और स्टूडेंट्स को वैल्यूएबल क्रॉस-कल्चरल लर्निंग एक्सपीरियंस देता है।**
- **राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ़ इकोनॉमिक स्टडीज़ (ASE)** से उनकी शानदार पब्लिक सर्विस, शिक्षा के प्रति कमिटमेंट, सोशल इन्क्लूजन और भारत-रोमानिया रिश्तों को मज़बूत करने के लिए **डॉक्टर ऑनोरिस कॉसा की ऑनरेरी डिग्री** मिली। उन्होंने यह सम्मान **भारत के 1.4 बिलियन लोगों को समर्पित किया और इसे दोनों देशों के बीच पक्की दोस्ती का प्रतीक बताया।** अपने भाषण के दौरान, उन्होंने **शिक्षा को सबसे बड़ा बराबरी लाने वाला बताया, अपने गाँव से राष्ट्रपति पद तक के अपने प्रेरणा देने वाले सफ़र के बारे में बताया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को नैतिकता, दया, ज्ञान और इंसानी मूल्यों के साथ बैलेंस करने पर ज़ोर दिया।**

- **NEET-UG परीक्षा** में कथित गड़बड़ियों को लेकर देश भर में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद **केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया।** अपने इस्तीफे में उन्होंने कहा कि यह फैसला स्टूडेंट्स के सबसे अच्छे हित में और भारत के एजुकेशन सिस्टम में भरोसा वापस लाने के लिए लिया गया था। उन्होंने स्टूडेंट्स की चिंताओं को माना, देश बनाने में **शिक्षा के महत्व पर ज़ोर दिया, परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ सरकारी कार्रवाई पर ज़ोर दिया** और प्रधानमंत्री और मंत्रालय के अधिकारियों को धन्यवाद दिया। इस विवाद ने **कंप्यूटर-बेस्ड परीक्षाओं, मज़बूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर मॉनिटरिंग सिस्टम और तेज़ी से शिकायत सुलझाने के तरीकों पर चर्चा को तेज़ कर दिया है।**
- **धर्मेन्द्र प्रधान** के इस्तीफे के बाद, **प्रल्हाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(2) के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस नियुक्ति को मंजूरी दी।** जोशी अपनी नई जिम्मेदारी के साथ-साथ **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और नई और रिन्यूएबल ऊर्जा मंत्रालय का काम भी संभालते रहेंगे।** **भाजपा के वरिष्ठ नेता और 2004 से धारवाड़ के सांसद, उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 को लागू करने में प्रधान की भूमिका की भी सराहना की।**
- **26 जुलाई 2026 को नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के एक लेटेस्ट AI होलोबॉक्स का उद्घाटन किया गया।** इस एग्जिबिशन में एक **हाइपर-रियलिस्टिक 3D AI अवतार है जो ऑर्थोटिकेटेड ऐतिहासिक रिकॉर्ड, भाषणों, लेखों और आर्काइवल मटीरियल का इस्तेमाल करके विज़िटर्स के साथ इंटरैक्ट कर सकता है।** उद्घाटन **27वें कारगिल विजय दिवस के साथ हुआ और इसमें माइक्रोफिल्म, ऐतिहासिक तस्वीरें, आर्काइवल वीडियो, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और पर्सनल लेटर** दिखाने वाली एक स्पेशल एग्जिबिशन शामिल थी। यह पहल दिखाती है कि **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे इमर्सिव एजुकेशनल एक्सपीरियंस बनाते हुए भारत की पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल और कल्चरल विरासत को बचा सकता है।**
- **भारत सरकार ने तीन साल के लिए एनहाइड्रस अमोनिया को फर्टिलाइज़र के तौर पर बनाने और खेती में इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है।** इसका मकसद **नाइट्रोजन के इस्तेमाल की क्षमता को बेहतर बनाना और यूरिया पर निर्भरता कम करना है।** इसमें लगभग **82% नाइट्रोजन होता है, यह बहुत ज्यादा गाढ़ा न्यूट्रिएंट सोर्स देता है, लेकिन इसके खतरनाक होने की वजह से इसके लिए खास इक्विपमेंट, सुरक्षित स्टोरेज और ट्रेंड हैंडलिंग की ज़रूरत होती है।** यह पहल सपोर्ट करती है **सस्टेनेबल खेती, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के साथ तालमेल बिठाती है, ग्रीन अमोनिया और ग्रीन यूरिया प्रोडक्शन को बढ़ावा देती है, फर्टिलाइज़र सिक््योरिटी को मजबूत करती है, इम्पोर्ट पर निर्भरता कम करती है, और पर्यावरण के अनुकूल खेती के तरीकों को बढ़ावा देती है।**

- बिहार में सिंचाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम (PMKSY-AIBP) के तहत कोसी - मेची इंटर-स्टेट लिंक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इस प्रोजेक्ट की बाकी लागत ₹6,143.22 करोड़ है, जिसमें से ₹3,652.56 करोड़ केंद्र की मदद से मिलेंगे, और इसे मार्च 2029 तक पूरा करने का प्लान है। इससे कोसी नदी से बचा हुआ पानी मेची बेसिन में जाएगा, पूर्वी कोसी मेन कैनाल को मॉडर्न बनाया जाएगा, सिंचाई का दायरा बढ़ाया जाएगा, पानी के इस्तेमाल की क्षमता में सुधार होगा, किसानों को मदद मिलेगी, खेती की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और पानी के टिकाऊ मैनेजमेंट को बढ़ावा मिलेगा।
- भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को नेशनल ऑनर (अमेंडमेंट) बिल, 2026, प्रिवेंशन ऑफ़ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, 1971 के तहत कानूनी सुरक्षा देने के लिए 24 जुलाई 2026 को राज्यसभा में पेश किया गया था। प्रस्तावित संशोधन इसे राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रीय गान के समान कानूनी ढांचे के तहत रखने की कोशिश करता है, साथ ही जानबूझकर इसे गाने से रोकने या बाधित करने के लिए सज़ा भी तय करता है। वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के जश्न के दौरान पेश किया गया यह बिल भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इसके ऐतिहासिक योगदान को मान्यता देता है और संसद की मंजूरी का इंतज़ार कर रहा है।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) ने 27 जुलाई 2026 को पृथ्वी भवन, नई दिल्ली में अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर मौसम की भविष्यवाणी, समुद्र पर रिसर्च, क्लाइमेट साइंस, पोलर एक्सप्लोरेशन और आपदा की तैयारी में दो दशकों की उपलब्धियों को दिखाया गया। 2006 में स्थापित इस मंत्रालय ने मिशन मौसम, पृथ्वी सिस्टम और डीप ओशन मिशन जैसे एडवांस्ड प्रोग्राम चलाए हैं। इस मौके पर AI-बेस्ड कोस्टल मॉनिटरिंग सिस्टम, अपग्रेडेड साइक्लोन वॉर्निंग फैसिलिटी, एडवांस्ड वेदर प्लेटफॉर्म और 13 सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस लॉन्च किए गए, जिससे साइंटिफिक इनोवेशन और पब्लिक सेफ्टी के लिए भारत का कमिटमेंट और मज़बूत हुआ।
- नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत कागज़ पर आधारित प्रक्रियाओं की जगह एक सुरक्षित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म लाकर पूरे भारत में कानूनी कामकाज को बदल रहा है। इसे "वन नेशन, वन एप्लीकेशन" के विज़न के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। NeVA लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स, प्रोसिडिंग्स और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कफ़्लो को डिजिटाइज़ करता है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, 37 में से 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लेजिस्लेचर ने MoU साइन किए हैं, जबकि 21 लेजिस्लेटिव हाउस पहले ही पूरी तरह से डिजिटल हो चुके हैं। यह प्लेटफॉर्म लेजिस्लेटर्स, अधिकारियों और नागरिकों के बीच ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, एक्सेसिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाता है, साथ ही पेपरलेस गवर्नेंस और लगातार टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड को बढ़ावा देता है।
- एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (APEDA) ने 30 जुलाई 2026 को कर्नाटक के नीलम और तोतापुरी आमों की पहली एयर शिपमेंट मालदीव भेजी। कोलार ज़िले से लगभग एक मीट्रिक टन आम अहिल्या देवी वेंचर्स की अश्विनी ए ने एक्सपोर्ट किया। APEDA के चेयरमैन अभिषेक देव ने इसे हरी झंडी दिखाई, इस पहल से किसानों को प्रीमियम एक्सपोर्ट प्राइसिंग के ज़रिए 50% से ज़्यादा ज़्यादा रिटर्न कमाने में मदद मिली। किसान प्रोड्यूसर कंपनियों (FPCs) के सपोर्ट से, इसने महिलाओं के नेतृत्व वाले एग्री-बिज़नेस को बढ़ावा दिया, ग्लोबल हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ावा, और किसानों की इनकम को मज़बूत किया।
- अहमदाबाद ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी के अपने विज़न को दिखाने के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के दौरान ग्लासगो में अहमदाबाद एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया। गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष सांघवी द्वारा खोला गया यह सेंटर अहमदाबाद के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, गुजरात की कल्चरल हेरिटेज और गेम्स के सौवें एडिशन की तैयारियों को दिखाता है। इसने एक दिन में एथलीट्स, डेलीगेट्स और स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स से 5,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवाए। लॉन्च में ट्रेडिशनल गरबा परफॉर्मेंस भी हुई, जबकि ब्रिटिश काउंसिल के साथ भविष्य की एजुकेशनल और कल्चरल पार्टनरशिप को मज़बूत करने पर बातचीत हुई।
- एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (APEDA) ने बिहार से कनाडा तक वैल्यू-एडेड फ्लेवर्ड मखाना (फॉक्स नट्स) की पहली समुद्री शिपमेंट को मुमकिन बनाया, जो भारत के एग्री-एक्सपोर्ट के लिए एक बड़ी कामयाबी है। न्यूट्रिविन द्वारा प्रोसेस किया गया 7-मेट्रिक-टन का कंसाइनमेंट एग्रो प्राइवेट लिमिटेड को दरभंगा से मुंद्रा पोर्ट के ज़रिए ZKV फ़ूड्स, कनाडा भेजा गया। इंटरनेशनल फूड सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से बनी यह पहल वैल्यू-एडेड एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट को बढ़ावा देती है, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और ग्लोबल मार्केट तक पहुँच को बेहतर बनाती है, साथ ही किसानों को 50% से ज़्यादा इनकम कमाने में मदद करती है।
- लोकसभा ने नेशनल ऑनर के अपमान की रोकथाम (अमेंडमेंट) बिल, 2026 पास कर दिया है, जिससे भारत के नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को कानूनी सुरक्षा मिलेगी। नेशनल ऑनर के अपमान की रोकथाम एक्ट, 1971 में यह संशोधन, इसके गाए जाने के दौरान जानबूझकर अपमान या रुकावट को सज़ा का अपराध बनाता है, और इसे नेशनल फ्लैग, संविधान और नेशनल एंथम को मिली सुरक्षा के बराबर रखता है। संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद, बिल को प्रेसिडेंट के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए वंदे मातरम ने भारत के आज़ादी के आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी।

- शशि थरूर की अध्यक्षता वाली विदेश मामलों की पार्लियामेंटी स्टैंडिंग कमिटी ने आर्कटिक और अंटार्कटिक मामलों में भारत की भागीदारी को मज़बूत करने के लिए एक डेडिकेटेड पोलर रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त करने की सिफारिश की। 30 जुलाई 2026 को पार्लियामेंट में पेश की गई, "आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में भारत की भूमिका और उपस्थिति" टाइटल वाली रिपोर्ट में पोलर डिप्लोमेसी, साइंटिफिक सहयोग और लॉन्ग-टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया। इसमें अंटार्कटिका में एक नए मैत्री रिसर्च स्टेशन के जल्द निर्माण की भी मांग की गई, जिसमें कहा गया कि पोलर क्षेत्रों में बदलाव भारत के क्लाइमेट, मानसून, समुद्र के लेवल और कोस्टल सिस्कोरिटी पर काफी असर डालते हैं।
- इंडियन रेलवे ने 31 जुलाई 2026 से कन्फर्म रिज़र्व टिकट वाले पैसेंजर के लिए ऑनलाइन पर्सनल लगेज बुकिंग की सुविधा शुरू की है। सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स (CRIS) का बनाया यह प्लेटफॉर्म पैसेंजर को टिकट रिज़र्व करते समय ज़्यादा लगेज ऑनलाइन बुक करने की सुविधा देता है, जिससे लगेज काउंटर पर जाने की ज़रूरत खत्म हो जाती है। यह सिस्टम फ्री बैगेज अलाउंस, मंज़ूर लिमिट, चार्ज, मना की गई चीज़ें और लागू पेनल्टी दिखाता है। फ्री लगेज लिमिट सेकंड क्लास में 35 kg से लेकर AC फर्स्ट क्लास में 70 kg तक है, जबकि बड़े साइज़ के लगेज को ब्रेक वैन में अलग से बुक करना होगा।
- अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के चार साल पूरे होने पर, भारत की 15वीं राष्ट्रपति और पहली आदिवासी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में कई नागरिक-केंद्रित और सस्टेनेबिलिटी-केंद्रित पहल शुरू कीं। इन पहलों में RAAHI (राष्ट्रपति भवन एक्सेस एंड हेरिटेज इंटरकनेक्टर) प्रोजेक्ट, एक एप्लीकेशन-बेस्ड ई-ऑडियो गाइड, ई-उपहार का तीसरा एडिशन, बच्चों के लिए बचपन - बाल परिसर, सर्विस ब्लॉक के लिए नेट ज़ीरो एनर्जी स्ट्रेटेजी और प्रेसिडेंट एस्टेट के अंदर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। इन पहलों का मकसद विज़िटर एक्सपीरियंस, हेरिटेज कंज़र्वेशन, डिजिटल गवर्नेंस, पब्लिक एंगेजमेंट और एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी को बेहतर बनाना है।
- वस्त्र उत्सव 2026, जिसे फ़ेड्स ऑफ़ दक्षिणचित्र (FOD) ने चेन्नई के पास दक्षिणचित्र म्यूज़ियम के लिए फंडरेज़र के तौर पर ऑर्गनाइज़ किया है, भारत की हैंडलूम विरासत, पारंपरिक क्राफ्ट और सस्टेनेबल फैशन का जश्न मनाता है। यह एग्ज़िबिशन देश भर के मास्टर बुनकरों, कारीगरों, डिज़ाइनरों, क्राफ्ट को फिर से ज़िंदा करने वालों और महिला एंटरप्रेन्योर्स को एक साथ लाती है। इसमें लगभग 50 स्टॉल्स हैं, जिनमें हाथ से बुने हुए कपड़े, नेचुरल फ़ाइबर, पारंपरिक रंगाई की तकनीक, SHG प्रोडक्ट, बाजरा से बने खाने की चीज़ें और देसी क्राफ्ट दिखाए जाते हैं। यह इवेंट कारीगरों की रोज़ी-रोटी, महिलाओं के एम्पावरमेंट, एथिकल फैशन और भारत की रिच टेक्सटाइल और कल्चरल विरासत के बचाव को बढ़ावा देता है।
- मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत घरेलू टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग को मज़बूत करने के लिए, भारत का पहला टेलीकॉम मैनुफैक्चरिंग ज़ोन (TMZ) ग्वालियर, मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार और डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकॉम्युनिकेशंस (DoT) के बीच एक MoU साइन किया जाएगा, जिसके बाद एक स्पेशल पर्पस कंपनी (SPC) बनाई जाएगी। 350 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट में मोबाइल फ़ोन, टेलीकॉम इक्विपमेंट, ऑप्टिकल फ़ाइबर, सेमीकंडक्टर, 5G और 6G प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। सेंट्रल फंडिंग में ₹493 करोड़ से सपोर्टेड, इससे ₹12,000-15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने और लगभग 5,000 डायरेक्ट जॉब्स बनने की उम्मीद है।
- भारत की सबसे पुरानी साइंटिफिक रिसर्च संस्था, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ़ साइंस (IACS) ने 2026 में अपने 150 साल पूरे कर लिए हैं। 29 जुलाई 1876 को कलकत्ता (अब कोलकाता) में डॉ. महेंद्रलाल सरकार ने इसे शुरू किया था। इस संस्था ने साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देने और भारतीय वैज्ञानिकों को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है। बंगाल पुनर्जागरण के दौरान, IACS ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैटेरियल्स साइंस में अहम योगदान दिया। इसकी सबसे ऐतिहासिक उपलब्धि सर सी.वी. रमन की 1928 में रमन इफेक्ट की खोज थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला। अभी डिपार्टमेंट ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (DST) के तहत काम कर रही IACS भारत में इनोवेशन और एडवांस्ड रिसर्च को बढ़ावा दे रही है।
- भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए विकसित भारत - रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) [VB-G RAM G एक्ट], 2025 के लिए ग्रामीण रोज़गार के लिए रिकॉर्ड ₹95,692 करोड़ आवंटित किए। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लोकसभा में घोषित, यह ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम के लिए अब तक का सबसे अधिक बजट अनुमान आवंटन है। इस अधिनियम ने MGNREGS की जगह ली और ग्रामीण परिवारों को सालाना 125 दिनों के मज़दूरी वाले रोज़गार की गारंटी देता है। यह जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे, आजीविका संपत्ति, जलवायु लचीलापन और सतत ग्रामीण विकास के लिए सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण पर केंद्रित है।
- इंडियन रेलवे ने 31 जुलाई 2026 को मुंबई सेंट्रल-गांधीनगर कैपिटल वंदे भारत एक्सप्रेस के ज़रिए भारत का पहला लाइव डोनर हार्ट सक्सेसफुली ट्रांसपोर्ट करके एक बड़ा माइलस्टोन हासिल किया। ऑर्गन को सूरत से अहमदाबाद ले जाया गया और एक क्रिटिकल ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के लिए यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ़ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर पहुंचाया गया। ट्रेन नंबर 20901 ने ज़रूरी ऑर्गन वायबिलिटी पीरियड के अंदर यह सफर पूरा किया। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) और गुजरात स्टेट पुलिस की मदद से अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से हॉस्पिटल तक एक स्पेशल ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। इस ऑपरेशन ने इमरजेंसी हेल्थकेयर लॉजिस्टिक्स में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती भूमिका को हाईलाइट किया और इसमें रेलवे अधिकारियों, डॉक्टरों, सिस्कोरिटी एजेंसियों और ट्रांसप्लांट टीमों के बीच कोऑर्डिनेशन शामिल था।

राज्य समाचार

- ओडिशा के पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन (SJTA) को भगवान जगन्नाथ से जुड़े पांच पवित्र नामों — जगन्नाथ धाम, श्रीक्षेत्र, महाप्रसाद, नीलचक्र और कोइली वैकुंठ — के लिए ट्रेडमार्क की मंजूरी मिल गई है। इस कदम का मकसद कमर्शियल गलत इस्तेमाल को रोकना और ट्रेडमार्क एक्ट, 1999 के तहत मंदिर की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखना है। यह पहल पश्चिम बंगाल के दीघा में एक मंदिर के लिए "जगन्नाथ धाम" नाम के इस्तेमाल पर हुए विवाद के बाद की गई है। SJTA ने जगन्नाथ विरासत से जुड़े 29 पवित्र नामों, निशानों और सांस्कृतिक चीजों के लिए भी ट्रेडमार्क सुरक्षा मांगी है।
- उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (WII) के साथ मिलकर, हरिद्वार कुंभ मेला 2027 से पहले झुंड में आगे बढ़ने वाले हाथियों को रेडियो-कॉलर लगाने की योजना बना रहा है ताकि इंसान-हाथी टकराव कम हो सके और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा बेहतर हो सके। मई 2026 से, रिसर्च राजाजी-कॉर्बेट हाथी इलाके में माइग्रेशन रूट, झुंड के साइज़ और हाथियों के व्यवहार की स्टडी कर रहे हैं। रियल-टाइम ट्रैकिंग से अधिकारियों को पहले चेतावनी जारी करने, बचाव टीमों को तैनात करने और बस्तियों के पास मुठभेड़ों को रोकने में मदद मिलेगी। इस प्रस्ताव को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी का इंतज़ार है। उत्तराखंड में 2020 की हाथी जनगणना में 2,026 हाथी दर्ज किए गए।
- राजस्थान सरकार ने "सहकार से समृद्धि" के विज़न के तहत जयपुर में भारत टैक्सी कोऑपरेटिव मोबिलिटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। यह प्लेटफॉर्म कोऑपरेटिव ओनरशिप, प्रॉफिट-शेयरिंग और सारथी कहे जाने वाले ड्राइवर्स को ट्रिप की कमाई के डायरेक्ट ट्रांसफ़र को बढ़ावा देता है। भारत टैक्सी के पास अभी 8 लाख रजिस्टर्ड ड्राइवर, 41 लाख कस्टमर हैं, और यह रोज़ाना लगभग 11,000 ट्रिप चलाता है, और इसे 500 शहरों में बढ़ाने का प्लान है। राजस्थान में, 30,000 से ज़्यादा सारथी और 7 लाख कस्टमर रजिस्टर्ड हैं। यह सर्विस ₹5 लाख का एक्सीडेंट इश्योरेंस भी देती है और रोज़गार, टूरिज़्म और शहरी ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करती है।
- मदुरै शहर ने सेल्लूर – कुलमंगलम रोड के पास एक ऐतिहासिक बरगद के पेड़ का 107वां जन्मदिन मनाया, जिसमें शहरी बायोडायवर्सिटी और पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर ज़ोर दिया गया। मीनाक्षीपुरम इलाके में इसे आखिरी सौ साल पुराना पेड़ माना जाता है, यह छाया देता है, पक्षियों के रहने की जगह को सहारा देता है, और तेज़ी से हो रहे शहरीकरण के बीच लोकल इकोसिस्टम को मज़बूत करता है। वॉटर बॉडी प्रोटेक्शन मूवमेंट और दूसरे ग्रुप्स द्वारा ग्रीन नेचर फेस्टिवल के तहत आयोजित इस इवेंट में पेड़ों की सजावट, पौधे बांटना, और जागरूकता प्रोग्राम शामिल थे, जिससे लोगों को प्राकृतिक विरासत और इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए बढ़ावा मिला।

- महाराष्ट्र, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) के तहत दूसरी किस्त के लिए कालिफ़ाई करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। इसने अपने शुरुआती एलोकेशन का 75% से ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है। पहले जारी किए गए ₹335 करोड़ में से, राज्य ने लगभग ₹260 करोड़ का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है, जो एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स के कुशल इम्प्लीमेंटेशन को दिखाता है। यह स्कीम एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज़, एनिमल हसबैंड्री, फ़ार्म मैकेनाइजेशन, डिजिटल फ़ार्मिंग और इंफ़्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे सेक्टरों को सपोर्ट करती है। RKVY-RAFTAAR के ज़रिए, यह एग्री-स्टार्टअप्स, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा देता है, जिससे किसानों की इनकम, प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।
- लेह में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोवा-रिंगपा (NISR) ने मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ योगा (MDNIY), नई दिल्ली के साथ मिलकर तीन महीने का, 400 घंटे का योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया। MDNIY की गाइडलाइंस के मुताबिक, इस प्रोग्राम का मकसद पूरे लद्दाख में योग शिक्षा, पूरी हेल्थकेयर और वेलनेस को बढ़ावा देना है। कोर्स का उद्घाटन वेन. भिक्खु संघसेना ने डॉ. ताशी थिनलास और डॉ. पद्मा गुरुमेट के साथ किया। यह थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को मिलाकर, पारंपरिक और मॉडर्न हेल्थकेयर सिस्टम को जोड़ता है और योग प्रोफेशनल्स के लिए नए मौके बनाता है।
- गुजरात सरकार ने साइबर फ़ाइनैशियल फ़्रॉड के मामलों की रिपोर्टिंग को आसान बनाने और पुलिस की कार्रवाई तेज़ करने के लिए 27 जुलाई 2026 को e-Zero FIR सिस्टम शुरू किया। गांधीनगर में डिप्टी चीफ़ मिनिस्टर हर्ष सांघवी ने इसे लॉन्च किया। यह प्लेटफॉर्म 1930 नेशनल साइबरक्राइम हेल्पलाइन से मिली शिकायतों को अपने आप e-Zero FIR में बदल देता है, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संबंधित पुलिस स्टेशनों को भेज दिया जाता है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) के साथ मिलकर बनाई गई इस पहल का मकसद रिस्पॉन्स टाइम को बेहतर बनाना, चोरी हुए पैसे वापस मिलने की संभावना बढ़ाना, साइबरक्राइम की जांच को मज़बूत करना और टेक्नोलॉजी पर आधारित पुलिसिंग को बढ़ावा देना है।
- गुजरात सरकार ने राज्य को भारत का सबसे बड़ा मैरीटाइम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए शिपबिल्डिंग और रिपेयर पॉलिसी 2026 लॉन्च की है, जिसमें ₹27,000 करोड़ से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट की उम्मीद है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा घोषित इस पॉलिसी का फोकस शिपबिल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाना, ग्रीन शिपयार्ड बनाना और स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए बड़े पैमाने पर रोज़गार पैदा करना है। इसमें पोर्बंदर में दो इंटीग्रेटेड मेगा शिपबिल्डिंग पार्क और एक ग्रीनफील्ड शिपबिल्डिंग क्लस्टर का प्रस्ताव है, जिसमें मॉडर्न शिपयार्ड, रिसर्च सेंटर, टेस्टिंग फैसिलिटी और लॉजिस्टिक्स इंफ़्रास्ट्रक्चर होगा। यह पहल इनोवेशन, एक्सपोर्ट, सस्टेनेबिलिटी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है, जिससे भारत की स्थिति एक ग्लोबल मैरीटाइम पावर के तौर पर मज़बूत होती है।

- छत्तीसगढ़ सरकार ने जुलाई 2026 में DWEEPTI (डीसेंट्रलाइज्ड वूमेन एम्पावरमेंट ऑन एनर्जी एंड पॉलिसी फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव इनक्लूजन) योजना शुरू की, जो भारत की पहली महिलाओं के नेतृत्व वाली डिस्ट्रिब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी (RE) पॉलिसी बन गई। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया (TRI) के साथ मिलकर इसे डेवलप किया है। इस स्कीम का मकसद 5,000 महिलाओं के नेतृत्व वाले सोलर एंटरप्राइज शुरू करना, 50,000 ग्रीन जॉब्स बनाना और 5 लाख परिवारों और 10,000 पब्लिक इंस्टीट्यूशन्स को क्लीन एनर्जी देना है। CSPDCL के साथ PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लागू की गई यह स्कीम "सोलर दीदियों" को ट्रेनिंग देती है, सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स (SHGs) को मज़बूत बनाती है, और महिलाओं के नेतृत्व वाली सोलर एंटरप्रेन्योरशिप और सस्टेनेबल ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देती है।
- कल्पसर प्रोजेक्ट, जिसे ऑफिशियली खंभात की खाड़ी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, गुजरात का एक बड़ा मल्टीपर्सन वॉटर इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है जिसका मकसद वॉटर सिक्वोरिटी, सिंचाई, कनेक्टिविटी और रिन्यूएबल एनर्जी जेनरेशन को बेहतर बनाना है। इस प्रोजेक्ट में खंभात की खाड़ी पर 64 km लंबा डैम बनाना शामिल है, जिससे लगभग 13,000 मिलियन क्यूबिक मीटर (MCM) कैपेसिटी वाला कोस्टल फ्रेशवाटर रिज़र्वॉयर बनाया जा सके। साबरमती, माही, ढाढर और नर्मदा नदियों से मिलने वाला यह प्रोजेक्ट सौराष्ट्र में लगभग 10 लाख हेक्टेयर में सिंचाई करेगा। इस प्रोजेक्ट में एक हाईवे-कम-रेल कॉरिडोर भी शामिल है, जो भावनगर-सूरत की दूरी को कम करेगा, और नीदरलैंड्स के सपोर्ट से 2,470 MW हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का प्लान है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अगस्त 2026 को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगापुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। GMR समूह द्वारा ₹5,000 करोड़ की लागत से निर्मित इस हवाई अड्डे का लक्ष्य उत्तरी आंध्र प्रदेश के लिए एक प्रमुख विमानन केंद्र बनना है। वाणिज्यिक परिचालन 17 अगस्त 2026 से शुरू होने वाला है। पहले चरण में सालाना 6 मिलियन यात्रियों को संभाला जाएगा, भविष्य में 40 मिलियन यात्रियों की क्षमता विस्तार के साथ। स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पर बना यह हवाई अड्डा पर्यटन, निर्यात, उद्योग, रोजगार और घरेलू-अंतरराष्ट्रीय संपर्क को बढ़ावा देगा। यात्रा के दौरान, ₹17,900 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन या शुभारंभ किया गया।
- पारंपरिक पिथौरा पेंटिंग को मशहूर जियोग्राफिकल इंडिकेशन (GI) टैग मिला है, जो राठवा आदिवासी समुदाय की पवित्र कला को कानूनी सुरक्षा और पहचान देता है। सदियों पुरानी यह दीवार पर बनी पेंटिंग बाबा पिथौरा को भेंट के तौर पर घर की दीवारों पर बनाई जाती है और इसमें देवी-देवताओं, घोड़ों, प्रकृति, गांव के जीवन और आध्यात्मिक निशानों को दिखाया जाता है। GI

स्टेटस बिना इजाज़त नकल को रोकता है और असली कलाकृतियों की सच्चाई पक्की करता है। इससे बाज़ार के मौके बेहतर होने, आदिवासी कारीगरों की इनकम बढ़ने, बिचौलियों पर निर्भरता कम होने और नई पीढ़ी को भारत की देसी सांस्कृतिक विरासत के इस ज़रूरी हिस्से को बचाने के लिए बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

- साउथ कोरिया के बुसान में हुए UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 48वें सेशन के दौरान, माउंट ओलिंपस (ग्रीस) और डी-डे लैंडिंग बीच (फ्रांस) को UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जोड़ा गया। ग्रीस की सबसे ऊंची चोटी, 2,918 मीटर की माउंट ओलिंपस को अपनी बहुत अच्छी नेचुरल बायोडायवर्सिटी और पौराणिक महत्व के लिए मिक्सड वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर पहचान मिली। नॉरमैंडी में डी-डे लैंडिंग बीच, जिसमें ओमाहा, यूटा, गोल्ड, जूनो, स्वॉर्ड बीच और पॉइंट डू होक शामिल हैं, को दूसरे वर्ल्ड वॉर में उनकी ऐतिहासिक भूमिका के लिए शामिल किया गया था। UNESCO ने क्लाइमेट चेंज, टूरिज्म और समुद्र के लेवल में बढ़ोतरी को लेकर भी चिंता जताई।
- कॉम्पिटियर फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने मार्केट डिस्टॉर्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स में अपनी रैंकिंग 2010 में 82वें स्थान से सुधारकर 2023 में 57वें स्थान पर पहुंचाई है, और 25 पोजीशन ऊपर आया है। रिपोर्ट में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST), इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC), रेगुलेटरी सिंपलिफिकेशन और ट्रेड फैसिलिटेशन उपायों जैसे सुधारों को मार्केट डिस्टॉर्शन को कम करने का क्रेडिट दिया गया है। इंडेक्स ओनरशिप राइट्स, घरेलू कॉम्पिटिशन और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस का आकलन करता है। नतीजे भारत की एक ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, कॉम्पिटिटिव और इन्वेस्टमेंट-फ्रेंडली इकोनॉमी की ओर हुई तरक्की को दिखाते हैं, साथ ही लंबे समय तक इकोनॉमिक ग्रोथ बनाए रखने के लिए लगातार स्ट्रक्चरल सुधारों की ज़रूरत पर ज़ोर देते हैं।
- प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के तहत US के सपोर्ट वाले शांति प्रस्ताव में, एक बड़े सीज़फ़ायर और रिकंस्ट्रक्शन प्लान के हिस्से के तौर पर गाज़ा में हमला और दूसरे मिलिटेंट ग्रुप्स के धीरे-धीरे हथियार खत्म करने की बात कही गई है। खबर है कि हमला ने इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मान लिया है, लेकिन इज़राइल ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अभी तक इसे औपचारिक मंजूरी नहीं दी है। मिस्र, क़तर और तुर्की की मध्यस्थता से बने इस प्लान में वेरिफाइड हथियार खत्म करना, इज़राइली सैनिकों की धीरे-धीरे वापसी, एक इंटरनेशनल स्टेबिलाइज़ेशन फ़ोर्स की तैनाती, एक नई फ़िलिस्तीनी पुलिस फ़ोर्स की स्थापना, और इंटरनेशनल लेवल पर निगरानी में रिकंस्ट्रक्शन शामिल है, जिसे आपसी सहमति पर निर्भर करते हुए लागू किया जाएगा।

- वेनेजुएला ने यूनाइटेड नेशंस (UN) को रोम स्टैच्यूट , जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) की संस्थापक संधि है , से हटने के अपने फैसले के बारे में औपचारिक रूप से बताया है । विदेश मंत्री फेलिक्स प्लासेंसिया ने कथित भौगोलिक भेदभाव पर चिंताओं का हवाला देते हुए इस कदम को "पक्का और अपरिवर्तनीय" कहा । और कोर्ट द्वारा असमान व्यवहार । रोम क़ानून के आर्टिकल 127 के तहत, वापसी एक साल बाद लागू होगी , और यह चल रही जांच को नहीं रोकेंगी, जिसमें 2021 में शुरू हुई वेनेजुएला में मानवता के खिलाफ कथित अपराधों की ICC जांच भी शामिल है । ICC, जिसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के हेग में है, नरसंहार, युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों और आक्रामकता की जांच करता है , और वेनेजुएला के बाहर निकलने से ग्लोबल जस्टिस सिस्टम के सामने बढ़ती चुनौतियां बढ़ गई हैं ।
- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 29 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में इंडियन कोस्ट गार्ड (ICG) के लिए दो बड़े सुधारों का ऐलान किया । इसका मकसद जेंडर इकालिटी को बढ़ावा देना और कर्मचारियों की भलाई को बेहतर बनाना है । नई पॉलिसी में जेंडर-न्यूट्रल ऑफिसर इंडक्शन फ्रेमवर्क लाया गया है , जिससे महिला ऑफिसर शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट (SSA) और परमानेंट अपॉइंटमेंट (PA) में शामिल हो सकती हैं , जबकि पुरुष उम्मीदवारों के लिए भी SSA खोला गया है । इन सुधारों से ICG को ड्यूटी के दौरान समुद्र में गायब होने की स्थिति में कर्मचारियों को "मृत मान लिया गया" घोषित करने का अधिकार भी मिला है, जिससे अगले रिश्तेदार (NoK) को एक्स-ग्रेटिया मुआवज़ा , टर्मिनल बेनिफिट और फाइनेंशियल मदद तेज़ी से मिल सकेगी । इन पहलों से समुद्री सुरक्षा में नारी शक्ति , सबको साथ लेकर चलने और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मज़बूती मिलेगी ।
- भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, जब उसकी पहली डायरेक्ट कमर्शियल कंटेनर फ्रेट ट्रेन रिवाइण्ड इंडिया-नेपाल रेल ट्रांजिट प्रोटोकॉल के तहत कैनोला का कंसाइनमेंट लेकर नेपाल पहुंची । यह ट्रेन कोलकाता पोर्ट (इंडिया) से विराटनगर (नेपाल) तक 40 वैगन के साथ चली और बॉर्डर ट्रांसशिपमेंट की ज़रूरतें खत्म हो गईं । इस पहल का मकसद ट्रांजिट टाइम, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और कार्गो हैंडलिंग को कम करना है, साथ ही सप्लाय चेन एफिशिएंसी में सुधार करना है । डायरेक्ट फ्रेट सर्विस इंडिया-नेपाल ट्रेड रिलेशन को मज़बूत करती है , रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देती है, और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत सस्टेनेबल रेल-बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन को सपोर्ट करती है ।
- पैसिफिक आइलैंड देश, जिसे पहले नाउरू के नाम से जाना जाता था, ने मई 2026 में पार्लियामेंट से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मंजूरी मिलने और 31 जुलाई 2026 को प्रेसिडेंट डेविड एडियांग से कन्फर्मेशन मिलने के बाद ऑफिशियली अपना नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ़ नाओरो कर लिया है । नाम बदलने का मकसद देश की लोकल पहचान को वापस लाना , खतरे में पड़ी नाउरू

भाषा (डोरैरिन) को बचाना है । नाओरो) , और सांस्कृतिक विरासत को मज़बूत करना । यूनाइटेड नेशंस को 26 जून 2026 को बताया गया और उसने ऑफिशियल रिकॉर्ड अपडेट करना शुरू कर दिया । देश का छोटा नाम अब नाओरो है , जबकि इसका कोड NRO बदला नहीं गया है । माइक्रोनेशिया में मौजूद यह देश लगभग 21 sq km में फैला है , यहाँ लगभग 12,000 लोग रहते हैं , यह ऑस्ट्रेलियन डॉलर इस्तेमाल करता है , और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर यारेन डिस्ट्रिक्ट है ।

बैंकिंग/अर्थव्यवस्था/व्यापार समाचार

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) , ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर , क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को तेज़ी से अपनाने की वजह से भारत रेड हैट के टॉप पांच ग्लोबल ग्रोथ मार्केट में से एक बन गया है । भारत और साउथ एशिया के वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर नवतेज सिंह बल के मुताबिक , देश रेड हैट और IBM के लिए एक बड़ा बिज़नेस , इंजीनियरिंग और इनोवेशन हब बन गया है । उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि AI नौकरियों की जगह लेने के बजाय प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा , जिससे AI , साइबर सिक्योरिटी , डेटा साइंस और क्लाउड टेक्नोलॉजी में स्किल्स की मांग बढ़ेगी, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत , AI डिप्लॉयमेंट और टैलेंट की कमी जैसी चुनौतियों पर भी ज़ोर दिया ।
- भारत सरकार ने देश के करेंसी सिस्टम को मॉडर्न बनाने के लिए एक अरब ₹10 और एक अरब ₹20 के पॉलीमर बैंकनोट के फील्ड ट्रायल करने के रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) के प्रपोज़ल को मंजूरी दे दी है । फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर पंकज चौधरी ने इस पहल की घोषणा की है । इस पहल में अलग-अलग मौसम और इस्तेमाल के हालात में नोटों की ड्यूरेबिलिटी , सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस को जांचा जाएगा । एक खास प्लास्टिक पॉलीमर से बने ये नोट नमी , गंदगी और घिसाव के लिए ज़्यादा रेज़िस्टेंट होते हैं , इनमें ज़्यादा मज़बूत एंटी-काउंटरफीटिंग फ़ीचर होते हैं और बदलने का खर्च कम होता है । पॉलीमर नोटों के साथ-साथ पेपर करेंसी भी चलती रहेगी, जबकि डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ेगा ।
- SBI लाइफ़ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2026 पैरा स्पोर्ट्स सीज़न के लिए पैरालंपिक कमेटी ऑफ़ इंडिया (PCI) की प्रिंसिपल पार्टनर बन गई है , जिससे इनक्लूसिव स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने और पैरा-एथलीटों को सपोर्ट करने का उसका कमिटमेंट और मज़बूत हुआ है । इस पार्टनरशिप के तहत, SBI लाइफ़ ग्लासगो में कॉमनवेल्थ पैरा गेम्स 2026 और ऐची-नागोया में एशियन पैरा गेम्स 2026 के लिए ऑफिशियल लाइफ़ इश्योरेंस पार्टनर के तौर पर काम करेगी । इस कोलेबोरेशन का मकसद एथलीटों की अचीवमेंट्स का जश्न मनाना, पैरा स्पोर्ट्स के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना और ज़्यादा पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना है । यह 2024 पेरिस पैरालंपिक गेम्स के दौरान इंडियन पैरा-एथलीटों के साथ अपने एसोसिएशन के बाद भी कंपनी का सपोर्ट जारी रखेगी ।

- मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी (MMA) ने 30 जुलाई 2026 को फवारा-UPI क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट कॉरिडोर लॉन्च किया, जिससे मालदीव के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से भारत में UPI-लिंकड बैंक अकाउंट में तुरंत पैसे ट्रांसफर किए जा सकेंगे। यह सिस्टम फवारा इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम को भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के साथ जोड़ता है, जिससे मालदीवियन रूफिया (MVR) अपने आप भारतीय रुपये (INR) में बदल जाता है। शुरुआत में बैंक ऑफ मालदीव Plc और मालदीव इस्लामिक बैंक Plc के ज़रिए उपलब्ध, इस पहल को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) के साथ मिलकर बनाया गया था, जिससे डिजिटल फाइनेंशियल कनेक्टिविटी और भारत-मालदीव आर्थिक सहयोग मजबूत हुआ।
- मिनिस्ट्री ऑफ़ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन (MoSPI) ने होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) की जगह आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (PPI) को तिमाही और सालाना GDP अनुमानों के लिए GDP डिप्लेटर के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया है, जहाँ भी लागू हो। DPIIT द्वारा जून 2026 में जारी किया गया PPI, प्रोड्यूसर प्राइस को बेहतर ढंग से दिखाता है और भारत को इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड्स के साथ जोड़ता है। यह सुधार डबल डिप्लेशन मेथड लाता है, GDP बेस ईयर को 2011-12 से 2022-23 तक अपडेट करता है, और इसे Q1 FY 2026-27 से लागू किया जाएगा, जिससे रियल GDP, GVA अनुमान और इकोनॉमिक पॉलिसीमेकिंग में सुधार होगा।
- Eroute Technologies Pvt. Ltd. द्वारा विकसित OmniCard ने भारत का पहला UPI-आधारित फ्लेक्सी बेनिफिट्स वॉलेट लॉन्च किया है, जिसे फ्लेक्सी बेनिफिट्स बास्केट कहा जाता है, जो RBI-लाइसेंस प्राप्त प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। वॉलेट कर्मचारियों को एकल डिजिटल वॉलेट के माध्यम से कर-कुशल लाभों का प्रबंधन करने और लगभग 60 मिलियन UPI-सक्षम व्यापारियों पर UPI स्कैन-एंड-पे लेनदेन करने में सक्षम बनाता है। भोजन, ईंधन, दूरसंचार, पुस्तकें और गैजेट्स जैसी श्रेणियों का समर्थन करते हुए, यह अनुपालन के लिए मर्चेट कैटेगरी कोड (MCC) नियंत्रण का उपयोग करता है। आयकर नियम, 2026 (1 अप्रैल 2026 से प्रभावी) के अनुरूप, यह भोजन के लिए ₹1,05,600 सहित सालाना ₹2 लाख से अधिक के कर-मुक्त लाभ प्रदान करता है।
- रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने ड्राफ्ट में बदलाव जारी किए हैं, जिसके तहत सभी सिक्वोरिटाइज़ेशन नोट्स (SNs) को सिर्फ़ डीमैट (डीमैट) फॉर्म में ही जारी, रखा और ट्रांसफर किया जाना ज़रूरी है। इससे ट्रांसपेरेंसी, लिक्विडिटी, एफ़िशिएंसी और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन बेहतर होगा। RBI ने जारी करने और बाद में ट्रांसफर करने, दोनों में कम से कम ₹1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लिमिट भी बनाए रखी है। यह प्रस्ताव लेंडर्स और स्पेशल पर्पस एंटीटीज़ (SPEs) के बीच कम्प्लायंस एग्रीमेंट को ज़रूरी बनाता है और पब्लिक इश्यू क्राइटेरिया को SEBI रेगुलेशंस के साथ जोड़ता है। इन सुधारों का मकसद भारत के सिक्वोरिटाइज़ेशन मार्केट को मॉडर्न बनाना, डेट मार्केट को मजबूत करना और इन्वेस्टर का भरोसा बढ़ाना है।
- सिंगापुर में हेडक्वार्टर वाला DBS बैंक, ग्लोबल फाइनेंस ग्लोबल बैंक अवार्ड्स 2026 में "वर्ल्ड्स बेस्ट कॉर्पोरेट बैंक" का टाइटल जीतने वाला पहला साउथईस्ट एशियन बैंक बन गया, जो 2005 में इस कैटेगरी के शुरू होने के बाद से पहला रीजनल विनर है। बैंक को कॉर्पोरेट बैंकिंग, डिजिटल इनोवेशन और फाइनेंशियल सर्विसेज़ में एक्सीलेंस के लिए "एशिया का बेस्ट बैंक" और "सिंगापुर का बेस्ट बैंक" अवार्ड भी मिला। 19 इंटरनेशनल मार्केट में ऑपरेट करते हुए, DBS कॉर्पोरेट फाइनेंस, ट्रेड फाइनेंस, कैश मैनेजमेंट और ट्रेजरी सर्विसेज़ में AI-ड्रिवन सॉल्यूशन देता है, जो सिंगापुर की ग्लोबल फाइनेंशियल लीडरशिप और बैंकिंग में एशिया की बढ़ती हेडक्वार्टरशिप को और मजबूत करता है।
- भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) को दुनिया भर में पहचान मिली है, जिसमें 24 देश इंडिया स्टैक को अपनाने के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं, जिसमें UPI, डिजिटलॉकर, आधार, ई-KYC, ईसाइन और अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क शामिल हैं। UPI अब 10 इंटरनेशनल मार्केट में मर्चेट पेमेंट के लिए उपलब्ध है, जबकि केन्या और क्यूबा ने डिजिटलॉकर को लागू करना शुरू कर दिया है। भारत, ई-संजीवनी, ई-ऑफिस और ई-हॉस्पिटल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को डिप्लॉय करने के लिए लाओस, सेशेल्स, वेनेजुएला, आर्मेनिया, फिजी, गुयाना और कोलंबिया के साथ भी बातचीत कर रहा है, जिससे डिजिटल गवर्नेंस, फाइनेंशियल इनक्लूजन और ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव में उसकी लीडरशिप मजबूत होगी।
- राज्यसभा में पेश किए गए वित्त मंत्रालय के डेटा के अनुसार, भारतीय बैंकों ने वित्त वर्ष 2025-26 में मिनिमम एवरेज बैलेंस (MAB) न रखने पर पेनल्टी के तौर पर ₹7,086.63 करोड़ इकट्ठा किए। प्राइवेट सेक्टर के बैंकों ने ₹4,948.71 करोड़ इकट्ठा किए, जो कुल चार्ज का लगभग 70% है, जबकि पब्लिक सेक्टर के बैंकों (PSB) ने ₹2,137.92 करोड़ इकट्ठा किए। HDFC बैंक और एक्सिस बैंक प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले बैंक थे। इस बीच, 12 में से 10 PSB ने सेविंग्स अकाउंट पर पेनल्टी बंद कर दी। बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट (BSBDA), जिसमें PM जन धन योजना अकाउंट भी शामिल हैं, मिनिमम बैलेंस की ज़रूरतों से मुक्त हैं। RBI ट्रांसपेरेंट और बोर्ड से मंज़ूर पॉलिसी के तहत ऐसे चार्ज की इजाज़त देता है।

- भारतीय स्टेट बैंक (SBI) 2026 में बेसल III-अनुपालन अतिरिक्त टियर- I (AT-1) सतत बॉन्ड जारी करने वाला पहला भारतीय बैंक बनने के लिए तैयार है , जिसका उद्देश्य अपने पूंजी आधार को मजबूत करना है। बैंक की योजना पांच साल के कॉल ऑप्शन के साथ बॉन्ड जारी करने के जरिए ₹5,000 करोड़ जुटाने की है , जो भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और नियामकों से अनुमोदन के अधीन है। यह जारी करना SBI की वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इंप्रोस्ट्रक्चर बॉन्ड, एटी-1 बॉन्ड और टियर- II बॉन्ड के माध्यम से ₹ 60,000 करोड़ की पूंजी जुटाने की बड़ी योजना का हिस्सा है । एटी-1 सतत बॉन्ड बैंकों को पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) में सुधार करने , बेसल III मानदंडों को पूरा करने , घाटे को अवशोषित करने और भविष्य की उधार वृद्धि का समर्थन करने में मदद करते हैं ।
- एक्सिस बैंक की पूरी तरह से मालिकाना हक वाली सब्सिडियरी कंपनी एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड (AFL) ने रिटेल और MSME लेंडिंग को बेहतर बनाने के लिए 'एक्सिस फाइनेंस दृष्टि' लॉन्च किया है । यह एक इन-हाउस बिजनेस रूल्स इंजन (BRE) और डिजिटल क्रेडिट डिसीजन प्लेटफॉर्म है । यह प्लेटफॉर्म तेज़, डेटा-ड्रिवन क्रेडिट असेसमेंट के लिए एडवांस्ड एनालिटिक्स, स्टैटिस्टिकल स्कोरकार्ड और कई डेटा सोर्स का इस्तेमाल करता है और रियल-टाइम डिसीजन-मेकिंग और स्ट्रेट-थ्रू प्रोसेसिंग (STP) को सपोर्ट करता है। फेज-I में , दृष्टि को पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी (LAP), और दिशा होम लोन के लिए शुरू किया गया था । AFL एक नॉन-डिपॉजिट लेने वाली NBFC है, जिसे 1995 में शामिल किया गया था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में है ।
- दिल्ली हाई कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) को बंद करने का ऐलान किया । RBI ने इस प्रोसेस को मैनेज करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) के पूर्व चीफ़ जनरल मैनेजर गिरिकुमार नायर को ऑफिशियल लिक्विडिटर अपॉइंट किया । यह एक्शन RBI के PPBL का लाइसेंस गंभीर रेगुलेटरी वायलेशन की वजह से कैंसिल करने के बाद लिया गया है । बैंक बंद करने का प्रोसेस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 और कंपनीज़ एक्ट, 2013 के तहत किया जाएगा । RBI ने भरोसा दिलाया कि डिपॉजिटर्स का पैसा सुरक्षित है और PPBL के पास लायबिलिटीज़ चुकाने के लिए काफ़ी लिक्विडिटी है।
- भारत का सकल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह जुलाई 2026 में ₹2.11 लाख करोड़ तक पहुंच गया , जिसमें बेहतर कर अनुपालन , मजबूत आर्थिक गतिविधि और बेहतर व्यावसायिक प्रदर्शन के कारण 15.4% की साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की गई। घरेलू जीएसटी संग्रह 10.1% बढ़कर ₹1.45 लाख करोड़ हो गया , जबकि आयात से जीएसटी 28.8% बढ़कर ₹66,511 करोड़ हो गया। ₹29,968 करोड़ के रिफंड के बाद , शुद्ध जीएसटी राजस्व ₹1.81 लाख करोड़ रहा , जो सालाना 15.8% बढ़ रहा है। अप्रैल-

- जुलाई वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान , कुल जीएसटी संग्रह ₹8.43 लाख करोड़ तक पहुंच गया । हरियाणा में सबसे अधिक 25% की वृद्धि दर्ज की गई , उसके बाद गुजरात और तेलंगाना में 19% की वृद्धि हुई।
- भारत का फिस्कल डेफिसिट FY 2026-27 की अप्रैल-जून तिमाही में ₹3.1 ट्रिलियन तक पहुंच गया , जो सरकार के ₹16.96 ट्रिलियन के सालाना टारगेट का 18.2% है। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंप्रोस्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर ज़्यादा सरकारी खर्च के कारण हुई । पिछले साल इसी समय के ₹2.8 ट्रिलियन की तुलना में , डेफिसिट प्लान्ड फिस्कल फ्रेमवर्क के अंदर रहा। सरकारी फाइनेंस को मजबूत रेवेन्यू कलेक्शन से सपोर्ट मिला, जिसमें नेट टैक्स रिसीट ₹5.4 ट्रिलियन से बढ़कर ₹6.4 ट्रिलियन हो गई , जबकि नॉन-टैक्स रेवेन्यू बढ़कर ₹3.8 ट्रिलियन हो गया । तिमाही के दौरान कुल सरकारी खर्च ₹13.6 ट्रिलियन तक पहुंच गया । डेटा FY27 के फिस्कल डेफिसिट टारगेट को GDP के 4.3% पर बनाए रखते हुए इन्वेस्टमेंट-लेड ग्रोथ पर लगातार फोकस दिखाता है ।
 - भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अनुसार, 24 जुलाई 2026 को खत्म हुए हफ्ते में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार \$6.12 बिलियन बढ़कर \$682.35 बिलियन हो गया। इस बढ़ोतरी को मुख्य रूप से फॉरेन करेंसी एसेट्स (FCAs) में बढ़ोतरी और ज़्यादा गोल्ड रिज़र्व से सपोर्ट मिला । FCAs \$4.87 बिलियन बढ़कर \$555.93 बिलियन हो गए , जबकि गोल्ड रिज़र्व \$1.31 बिलियन बढ़ा । हालांकि, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) के साथ स्पेशल ड्राइंग राइट्स (SDRs) \$53 मिलियन घटकर \$18.62 बिलियन हो गए , और भारत का IMF रिज़र्व पोझिशन \$11 मिलियन घटकर \$4.75 बिलियन हो गया। मजबूत फॉरेक्स रिज़र्व रुपये की स्थिरता बनाए रखने , इम्पोर्ट पेमेंट को सपोर्ट करने, बाहरी ज़िम्मेदारियों को मैनेज करने और इकोनॉमी को ग्लोबल फाइनेंशियल अनिश्चितताओं से बचाने में मदद करते हैं ।

समझौते/MoU

- आयुष मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत IndiaAI मिशन ने 31 जुलाई 2026 को भारत के पारंपरिक हेल्थकेयर सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को जोड़ने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर साइन किए। इस सहयोग से आयुर्वेद , योग और नेचुरोपैथी , यूनानी , सिद्ध और होम्योपैथी में AI-ड्रिवन रिसर्च , डिजिटल हेल्थकेयर , औषधीय पौधों की स्टडी , ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा । मुख्य पहलों में AIKosh प्लेटफॉर्म , GPU-बेस्ड हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और IndiaAI इनोवेशन चैलेंज 2026 शामिल हैं , जो रिसर्चर्स, स्टार्टअप्स और सबूतों पर आधारित हेल्थकेयर को सपोर्ट करते हैं।

नियुक्तियाँ/इस्तीफ़े

- 1995 के AGMUT कैडर के IAS ऑफिसर श्री केशव चंद्रा ने 27 जुलाई 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ़ माइंस के सेक्रेटरी का पद संभाला। ऑफिस संभालने के तुरंत बाद, उन्होंने **मिनरल एक्सप्लोरेशन, मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी और ज़रूरी और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के डेवलपमेंट** से जुड़े खास प्रोग्राम्स का असेसमेंट करने के लिए एक रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की। उन्होंने माइनिंग रिफॉर्म को असरदार तरीके से लागू करने, स्टेकहोल्डर्स के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन और **भारत की मिनरल सिक्योरिटी को मज़बूत करने पर ज़ोर दिया।** मिनिस्ट्री इलेक्ट्रिक गाड़ियों, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए **लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स** जैसे मिनरल्स को प्रायोरिटी दे रही है।
- विदेश मंत्रालय (MEA) ने सैन फ्रांसिस्को में भारत के वर्तमान महावाणिज्यदूत डॉ. के. श्रीकर रेड्डी को कतर में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब **भारत-कतर संबंध ऊर्जा, व्यापार, निवेश, तकनीक और रणनीतिक सहयोग में विस्तार कर रहे हैं।** कतर भारत का सबसे बड़ा लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) आपूर्तिकर्ता बना हुआ है, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 11.2 मिलियन टन या भारत के LNG आयात का 41% योगदान देगा। दोनों देशों ने फरवरी 2025 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को \$14 बिलियन से \$28 बिलियन तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है।
- वर्षा अशोक अगलावे 31 जुलाई 2026 को 54वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालने के बाद **भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनीं।** उनकी नियुक्ति ने GSI के 176 साल के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण को चिह्नित किया और भारत के वैज्ञानिक नेतृत्व में महिलाओं के बढ़ते योगदान को उजागर किया। उन्होंने **असित साहा का स्थान लिया** और उनके पास **भूविज्ञान, भूवैज्ञानिक अन्वेषण और प्रशासन में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है।** अगलावे भारतीय खान ब्यूरो के साथ काम करने के बाद 1992 में GSI में शामिल हुईं और इससे पहले कोलकाता के पूर्वी क्षेत्र के अतिरिक्त महानिदेशक और विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। जीवाश्म विज्ञान और जीवाश्म विज्ञान की विशेषज्ञ, उन्होंने मध्य भारत में सालबर्डी-घोरपेंड डायनासोर के घोंसले के शिकार स्थल की पहचान करने में योगदान दिया।
- केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) के अध्यक्ष के रूप में **के. राजारमन का कार्यकाल 24 अक्टूबर 2028 तक बढ़ा दिया है।** विस्तार की घोषणा वित्त मंत्रालय के राजपत्र अधिसूचना दिनांक 30 जुलाई 2026 के माध्यम से की गई, जो 2023 में शुरू होने वाले उनके मूल तीन साल के कार्यकाल में 27 महीने जोड़ता है। राजारमन, एक वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी और दूरसंचार विभाग के पूर्व सचिव, GIFT अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (GIFT IFSC), गांधीनगर के विकास

का मार्गदर्शन करना जारी रखेंगे। IFSCA अधिनियम, 2019 के तहत अप्रैल 2020 में स्थापित, प्राधिकरण बैंकिंग, बीमा, पूंजी बाजार और धन सहित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं को नियंत्रित करता है। उनके निरंतर नेतृत्व का उद्देश्य वैश्विक निवेश को आकर्षित करना और अंतर्राष्ट्रीय वित्त में भारत की स्थिति को मजबूत करना है।

रक्षा समाचार

- भारत एक देश में बना एंटी-स्वार्म ड्रोन डिफेंस सिस्टम है** जिसे दुश्मन के ड्रोन और घूम रहे हथियारों को बेअसर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे 24 जुलाई 2026 को नागपुर में मेक-II प्रोजेक्ट लॉन्च के दौरान भारतीय सेना को दिखाया गया था। यह मोबाइल और सस्ता सिस्टम रियल-टाइम खतरे का पता लगाने और ट्रैकिंग के लिए रडार, EO/IR सेंसर, पैसिव RF डिटेक्टर और C4I सिस्टम को जोड़ता है। यह दो-लेयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जिसमें ड्रोन झुंड के खिलाफ मिनी-रॉकेट और 2.5 km तक सटीक हमले के लिए स्मार्ट मिनी-मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। यह सिस्टम 10 km से बड़े UAV और 6 km से छोटे ड्रोन का पता लगा सकता है, साथ ही भारत के लेयर्ड एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए सॉफ्ट-किल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को हार्ड-किल हथियारों के साथ जोड़ता है।
- थल सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ ने 31 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में स्वदेशी रूप से विकसित **एक्सटीएम वेदर ग्रेड (XWG) डीज़ल लॉन्च किया, ताकि ऊंचाई वाले और बर्फ़ीले क्षेत्रों में सैन्य गतिशीलता में सुधार हो सके।** भारतीय सेना और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित, यह विशेष ईंधन -42 डिग्री सेल्सियस जैसे कम तापमान पर कुशलता से काम करता है, जिससे इंजन की विफलताओं और ईंधन फिल्टर की रुकावटों को रोका जा सकता है। सेना के मौजूदा वाहन बेड़े के अनुकूल, यह ईंधन BS-VI उत्सर्जन मानदंडों और IS 1460:2025 मानकों का अनुपालन करता है, जो रणनीतिक सीमा क्षेत्रों में रक्षा रसद, परिचालन तैयारी और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करता है।
- भारतीय नौसेना ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) द्वारा निर्मित आठ एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (एसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी) में से सातवें मछलीपट्टनम को लॉन्च किया, जो भारत की तटीय सुरक्षा और समुद्री रक्षा क्षमताओं को बढ़ाता है। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ, पोत आत्मनिर्भर भारत पहल का समर्थन करता है और इसे पानी के नीचे निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध (एसडब्ल्यू), कम तीव्रता वाले समुद्री संचालन (लिमो) और माइन वारफेयर के लिए डिज़ाइन किया गया है। आंध्र प्रदेश के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर मछलीपट्टनम के नाम पर, यह शिल्प समुद्री डोमेन जागरूकता को मजबूत करेगा, रणनीतिक समुद्री लेन की रक्षा करेगा और हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में परिचालन तत्परता में सुधार करेगा।

- भारत सरकार ने सशस्त्र सीमा बल (SSB) भर्ती नियम, 2026 को नोटिफाई किया है, जिसमें अग्रिपथ स्कीम के तहत अपनी सर्विस पूरी करने वाले एक्स-अग्रिवीरों के लिए कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) की 50% वैकेंसी रिज़र्व की गई है। नए नियम रिक्रूटमेंट में बड़ी छूट देते हैं, जिसमें रिटन एग्जाम, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST), और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) से छूट शामिल है, जबकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरतें बनी रहेंगी। एक्स-अग्रिवीरों को पहले बैच के लिए 5 साल और बाद के बैच के लिए 3 साल की छूट मिलेगी। इस सुधार का मकसद सर्विस के बाद के रोज़गार के मौकों को सपोर्ट करना और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPFs) को मज़बूत करना है। SSB मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स (MHA) के तहत काम करता है और नेपाल और भूटान के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा करता है।
- एयर मार्शल संदीप थरेजा को 31 अगस्त 2026 से प्रभावी, भारतीय सशस्त्र बलों में सर्वोच्च चिकित्सा पद, महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (DGAFMS) के रूप में नियुक्त किया गया है। वह सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन की सेवानिवृत्ति के बाद उनका स्थान लेंगे। थरेजा ने पहले महानिदेशक चिकित्सा सेवा (वायु) के रूप में कार्य किया और सैन्य चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा प्रशासन और परिचालन चिकित्सा सहायता में लगभग चार दशकों का अनुभव रखते हैं। AFMC पुणे के स्नातक, उन्होंने मेडिसिन में MD और AIIMS नई दिल्ली से गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में DM की डिग्री प्राप्त की है, जहाँ उन्हें सर्वश्रेष्ठ DM छात्र का पुरस्कार मिला था। उन्होंने प्रमुख सैन्य अस्पतालों की कमान संभाली है, AFMC के कमांडेंट के रूप में कार्य किया है और गगनयान और BHISHM क्यूब पहल जैसे मिशनों के लिए स्वास्थ्य सेवा तैयारियों में योगदान दिया है।
- भारतीय वायु सेना के उप वायु सेना प्रमुख (डीसीएएस), एयर मार्शल एके भारती कई दशकों के विशिष्ट सैन्य करियर के बाद 31 जुलाई 2026 को सेवानिवृत्त हुए। 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की तीनों सेनाओं की मीडिया ब्रीफिंग के सार्वजनिक चेहरे के रूप में उन्हें राष्ट्रीय पहचान मिली। महानिदेशक वायु संचालन (डीजीएओ) के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने महत्वपूर्ण हवाई अभियानों की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने और परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सेना और नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संयुक्त ब्रीफिंग के दौरान भारतीय वायु सेना का प्रतिनिधित्व किया, रणनीतिक विकास और सैन्य अभियानों की व्याख्या की। सेवानिवृत्ति से पहले, उन्होंने डीसीएएस के रूप में भारतीय वायुसेना के सर्वोच्च नेतृत्व वाले पदों में से एक पर कार्य किया।

पुरस्कार और सम्मान

- पूर्व चेयरमैन डॉ. जी. सतीश रेड्डी को डिफेंस रिसर्च, साइंटिफिक इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता में उनके शानदार योगदान के लिए हैदराबाद में प्रतिष्ठित EMESCO-डॉ. BV पट्टाभिराम चेंजमेकर-2026 अवॉर्ड मिला। यह अवॉर्ड एक्टर और पॉलिटिशियन चिरंजीवी ने दिया। डॉ. रेड्डी ने स्वदेशी डिफेंस टेक्नोलॉजी में भारत की बढ़ती क्षमताओं पर जोर दिया, जिससे ज़रूरी मिलिट्री सिस्टम के लिए विदेशी देशों पर निर्भरता काफी कम हो गई है। नेशनल सिव्कोरिटी एडवाइजरी बोर्ड (NSAB) के सदस्य के तौर पर, वे साइंस आउटरीच, लेक्चर और इनोवेशन से जुड़ी पहलों के ज़रिए स्टूडेंट्स और युवा साइंटिस्ट्स को प्रेरित करते रहते हैं।
- इलेक्ट्रिक मर्चेन्ट्स एसोसिएशन (EMA) के 2025-26 के प्रेसिडेंट प्रेम के. वोरा को जुलाई 2026 में नई दिल्ली में हुए नेशनल लीडरशिप कॉन्क्लेव के दौरान प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अशोक सम्मान (भारत सम्मान) से सम्मानित किया गया। यह अवॉर्ड इलेक्ट्रिकल ट्रेड सेक्टर, एथिकल बिज़नेस प्रैक्टिस, MSME डेवलपमेंट और सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ में उनके शानदार योगदान को पहचान देता है। उनके नेतृत्व में, EMA ने इंडस्ट्री में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रीन इलेक्ट्रिकल्स इनिशिएटिव, इनोवेशन और मॉडर्नाइज़ेशन को बढ़ावा दिया है। उन्हें पहले ग्लोबल यूथ एंबेसडर अवॉर्ड और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री अवॉर्ड में आइकॉनिक इमर्जिंग लीडर जैसे सम्मान मिल चुके हैं।
- मैथेमेटिक्स में सबसे बड़ा सम्मान माना जाने वाला फील्ड्स मेडल 2026, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ़ मैथेमेटिशियंस (ICM) 2026 में हांग वांग, यू डेंग, जॉन पार्डन और जैकब सिमरमैन को दिया गया। यह अवॉर्ड खास मैथेमेटिकल अचीवमेंट्स और भविष्य की संभावनाओं को पहचानता है। हांग वांग को हार्मोनिक एनालिसिस और जियोमेट्रिक मेज़र थ्योरी में योगदान के लिए सम्मानित किया गया, जबकि यू डेंग को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन (PDEs) में काम के लिए मिला। जॉन पार्डन को सिम्पलेक्टिक ज्योमेट्री और टोपोलॉजी के लिए, और जैकब सिमरमैन को अरिथमेटिक ज्योमेट्री में तरक्की के लिए सम्मानित किया गया। फील्ड्स मेडल हर चार साल में इंटरनेशनल मैथेमेटिकल यूनियन (IMU) द्वारा 40 साल से कम उम्र के मैथेमेटिशियंस को दिया जाता है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक मामलों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 1 अगस्त 2026 को पुणे, महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 मिला। यह पुरस्कार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि पर लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक समारोह के दौरान प्रदान किया। डोभाल को खुफिया अभियानों, आतंकवाद, सीमा सुरक्षा और सुरक्षा नीति निर्माण में दशकों से चली आ रही उनकी सेवा के लिए मान्यता दी गई थी। 1968 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी, वे भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। सम्मान में एक स्मृति चिह्न, प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपये नकद पुरस्कार शामिल

रैंक और रिपोर्ट समाचार

- BIMCO-ICS सीफ्रेयरर वर्कफ़ोर्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीफ्रेयरर सप्लायर बन गया है, जिसमें 311,936 मैरीटाइम प्रोफेशनल और ग्लोबल सीफ्रेयरिंग वर्कफ़ोर्स का 12.16% हिस्सा है। भारत फिलीपींस के बाद और चीन, रूस और इंडोनेशिया से आगे है। मैरीटाइम एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी की वजह से भारत का ग्लोबल शेयर 2015 में 5.2% से बढ़कर 2026 में 12.16% हो गया। यह रिपोर्ट BIMCO (बाल्टिक एंड इंटरनेशनल मैरीटाइम काउंसिल) और ICS (इंटरनेशनल चैंबर ऑफ़ शिपिंग) ने तैयार की है, जो ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री में भारत की बढ़ती भूमिका को दिखाती है।
- येल सेंटर फॉर एनवायरनमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के CIESIN और येल सेंटर फॉर जियोस्पेशियल सॉल्यूशंस द्वारा तैयार एनवायरनमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स (EPI) 2026 ने क्लाइमेट चेंज, एयर क्वालिटी, बायोडायवर्सिटी, वॉटर रिसोर्स और इकोसिस्टम हेल्थ को कवर करने वाले 47 इंडिकेटर्स के आधार पर 177 देशों का मूल्यांकन किया। एस्टोनिया 74.79 स्कोर के साथ रैंकिंग में टॉप पर रहा, जबकि भारत 22.46 स्कोर के साथ 176वें स्थान पर रहा, जो केवल लाओस से ऊपर है। रिपोर्ट में पॉल्यूशन, इकोसिस्टम कंजर्वेशन और सस्टेनेबिलिटी से जुड़ी चुनौतियों पर रोशनी डाली गई है, हालांकि भारत पहले भी EPI मेथड और डेटा असेसमेंट प्रोसेस पर सवाल उठा चुका है।

खेल समाचार

- भारत की अनाहत सिंह ने वर्ल्ड जूनियर स्कैश चैंपियनशिप 2026 में लड़कियों का सिंगल्स टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। नई दिल्ली की 18 साल की इस खिलाड़ी ने मिस्स की रुकैया सलेम को हराया। फाइनल में 3-0 (11-3, 11-7, 11-9) से जीत हासिल की। उन्होंने छह मैचों में सिर्फ दो गेम हारकर टूर्नामेंट में अपना दबदबा बनाया और मिस्स की 13 साल की जीत का सिलसिला खत्म किया, और 2010 के बाद पहली गैर-मिस्स चैंपियन बनीं। अनाहत, जिन्होंने स्कैश में आने से पहले बैडमिंटन खेला था, ने 2005 में जोशना चिनप्पा के पिछले सबसे अच्छे प्रदर्शन को पीछे छोड़ दिया, जो भारतीय स्कैश के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है।
- भारतीय वेटलिफ्टिंग स्टार मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं की 48 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। 2018, 2022 और 2026 में जीत के बाद यह उनका लगातार तीसरा कॉमनवेल्थ गेम्स का टाइटल है। 31 साल की मीराबाई ने कुल 190 kg वज़न उठाया, जिसमें सैच में 85 kg और क्लीन एंड जर्क में 105 kg वज़न शामिल है। इससे भारत को इन गेम्स का पहला गोल्ड मेडल मिला। नाइजीरिया की रूथ असुको न्योंग ने सिल्वर

मेडल जीता, जबकि मलेशिया की आइरीन जेन हेनरी ने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता। एक ओलंपिक सिल्वर मेडल और कई वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल के साथ, मीराबाई भारतीय खेलों को प्रेरित करती रहती हैं।

- इंडियन वेटलिफ्टर राजा मुथुपंडी ने ग्लासगो में 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों की 65 kg कैटेगरी में कुल 286 kg उठाकर सिल्वर मेडल जीता। वह मलेशिया के अज़नील बिन बिदिन मुहम्मद से पीछे रहे, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स के रिकॉर्ड 299 kg के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि पापुआ न्यू गिनी के मोरिया बारू ने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता। राजा ने एक मुश्किल सैच कोशिश और एक फेल क्लीन एंड जर्क लिफ्ट से उबरने के बाद कमाल का पक्का इरादा दिखाया। पिछली चोटों से उनकी वापसी ने गेम्स में इंडिया के वेटलिफ्टिंग कैपेन को और मज़बूत किया।
- ऋषिकांत सिंह चनंबम ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों के 60 kg वेटलिफ्टिंग इवेंट में सिल्वर मेडल जीतकर पहले भारतीय मेडलिस्ट बने। मणिपुर के इफाल वेस्ट के एथलीट ने सैच में 121 kg और क्लीन एंड जर्क में 143 kg उठाकर कुल 264 kg उठाकर नया कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड बनाया। मलेशिया के मोहम्मद अनीक कसदन ने 273 kg के साथ गोल्ड जीता, जबकि जोशुआ अमुंगा म्बोया ने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता। इससे पहले, ऋषिकांत ने 2025 कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था, जिससे उन्होंने इंटरनेशनल स्टेज पर अपनी कंसिस्टेंसी दिखाई थी।
- निक डी ग्रीस ने ABB FIA फॉर्मूला E वर्ल्ड चैंपियनशिप के टोक्यो E-Prix की दूसरी रेस में महिंद्रा रेसिंग के लिए जीत पक्की की, जिससे टीम का चैंपियनशिप कैपेन और मज़बूत हुआ। पांचवें स्थान से शुरुआत करते हुए, उन्होंने गीले-से-सूखे ट्रैक की कंडीशन को अच्छे से संभाला, स्ट्रेटजी के साथ अटैक मोड का इस्तेमाल किया, और देर से रेड फ्लैग रीस्टार्ट के बाद अपनी बढ़त बनाए रखी। यह जीत 2026 सीज़न की उनकी दूसरी जीत और महिंद्रा रेसिंग की साल की दूसरी जीत थी, 2017-18 के बाद यह उनका पहला मल्टी-विन सीज़न था। टीम ने टोक्यो डबल-हेडर के दौरान 38 पॉइंट्स इकट्ठा किए और 210 पॉइंट्स के साथ टीम चैंपियनशिप में चौथे स्थान पर पहुंच गई, जबकि टीम के साथी एडोआर्डो मोर्तारा दूसरे स्थान पर रहे। सीज़न के पोल-पोज़िशन रिकॉर्ड की बराबरी की।
- भारतीय एथलीट सर्वेश अनिल कुशारे ने ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों की हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने अपनी आखिरी कोशिश में 2.25 मीटर की बेस्ट जंप लगाई। हालांकि वह 2.28 मीटर की जंप लगाने से चूक गए, लेकिन उनके परफॉर्मेंस ने भारत को इस इवेंट में अब तक का सबसे अच्छा रिजल्ट दिलाया, और पिछले ब्रॉन्ज़ मेडल की अचीवमेंट को पीछे छोड़ दिया। जमैका के रोमेन बेकफोर्ड ने काउंटबैक पर गोल्ड मेडल जीता, जबकि स्कॉटलैंड के जैक किमानी ने 2.20 मीटर के साथ ब्रॉन्ज़ मेडल जीता। यह अचीवमेंट इंटर-स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2.31 मीटर की नेशनल रिकॉर्ड जंप के बाद कुशारे के शानदार फॉर्म में शामिल है।

- इंडियन वेटलिफ्टर अजय बाबू ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों के 79 kg इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने कुल 330 kg वज़न उठाया, जिसमें स्नैच में 149 kg और क्लीन एंड जर्क में 181 kg शामिल थे। वह गोल्ड मेडल से सिर्फ 1 kg से चूक गए, क्योंकि मलेशिया के एरी हिदायत मुहम्मद ने कॉमनवेल्थ गेम्स के रिकॉर्ड 331 kg के साथ जीत हासिल की, जबकि इंग्लैंड के क्रिस मरे ने 325 kg के साथ ब्रॉन्ज़ मेडल जीता। अजय का मेडल गेम्स में इंडिया का छठा वेटलिफ्टिंग मेडल बन गया, जिससे इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में देश की रेप्यूटेशन और मज़बूत हुई।
- इंडियन वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं की 53 kg कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता, और गेम्स में इंडिया की चौथी वेटलिफ्टिंग मेडलिस्ट और ओवरऑल पांचवीं मेडलिस्ट बन गई। उन्होंने स्नैच में 88 kg और क्लीन एंड जर्क में 111 kg वज़न उठाकर कॉमनवेल्थ गेम्स के रिकॉर्ड बनाए, इससे पहले नाइजीरिया की ओनोमे ओमोलोला ने उन्हें पीछे छोड़कर गोल्ड जीता, जबकि कनाडा की रेबेका ग्रावल्स ने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता। छत्तीसगढ़ पुलिस में असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर, ज्ञानेश्वरी ने एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भी मेडल जीते हैं और उनके नाम एक नेशनल रिकॉर्ड भी है, जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में उनकी लगातार सफलता को दिखाता है।
- भारतीय शूटर ईशा सिंह ने चीन के हांगजो में ISSF वर्ल्ड कप 2026 में महिलाओं की 25m पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने फाइनल में चीन की झांग यूयुए को 40-37 से हराया। इस जीत से उन्हें रोम में ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2026 के लिए सीधे क्वालिफिकेशन भी मिल गई। साथी भारतीय शूटर और ओलंपियन मनु भाकर ने करीबी मुकाबले वाले शूट-ऑफ के बाद 28 हिट के साथ ब्रॉन्ज़ मेडल जीता। दोनों एथलीटों के शानदार प्रदर्शन ने इंटरनेशनल शूटिंग में, खासकर महिलाओं की पिस्टल इवेंट में, भारत की साख को और मज़बूत किया, जिससे ग्लोबल स्टेज पर देश का बढ़ता दबदबा दिखा।
- भारत ने 30 जुलाई 2026 को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष और महिला दोनों टीम खिताब जीतकर ऐतिहासिक दोहरी उपलब्धि हासिल की। पुरुष टीम ने मलेशिया को 3-2 से हराया, जिसमें मानुष शाह ने निर्णायक मुकाबले सहित दो महत्वपूर्ण एकल मैच जीते। महिला टीम पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रही और स्वास्तिका घोष, श्रीजा अकुला और यशस्विनी घोरपड़े की जीत की मदद से फाइनल में मलेशिया को 3-0 से हराया। 27 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित इस चैंपियनशिप में भारत को 10,000 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि मिली और राष्ट्रमंडल के सबसे मज़बूत टेबल टेनिस राष्ट्रों में से एक के रूप में इसका दर्जा मज़बूत हुआ।
- भारतीय वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों की +110 kg कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता, गोल्ड मेडल से सिर्फ एक किलोग्राम से चूक गए। 28 साल के लवप्रीत ने कुल 388 kg वज़न उठाया, जिसमें कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड भी शामिल है। 176 kg स्नैच और 212 kg क्लीन एंड जर्क। न्यूज़ीलैंड के डेविड लिटी ने क्लीन एंड जर्क में 223 kg उठाकर रिकॉर्ड 389

- kg कुल वज़न के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि लवप्रीत अपनी आखिरी कोशिश में 217 kg वज़न नहीं उठा पाए। उनके मेडल की मदद से भारत ने वेटलिफ्टिंग में आठ मेडल के साथ अपना सफल कैपेन खत्म किया, जबकि मार्टिना देवी मैबाम महिलाओं की +86 kg कैटेगरी में पांचवें स्थान पर रहीं।
- भारतीय एथलीट सीमा कालीरमना ने ग्लासगो में 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं की डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज़ मेडल जीता, और 58.66 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ अपना पहला बड़ा इंटरनेशनल मेडल हासिल किया। जमैका की सामंथा हॉल ने 61.66 मीटर के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि कनाडा की जूलिया टंक्स ने 60.67 मीटर के साथ सिल्वर मेडल जीता। 27 साल की PhD स्कॉलर और चार साल के बेटे की माँ, सीमा ने दो साल के ब्रेक के बाद एक इंस्पायरिंग वापसी की, और 2026 में पहले 59.73 मीटर का पर्सनल बेस्ट हासिल किया। उनके ब्रॉन्ज़ मेडल ने भारत के एथलेटिक्स मेडल की संख्या चार कर दी, जो उनके पक्के इरादे और लगन को दिखाता है।
- पूर्व कप्तान अजिंक्य रहाणे, जिन्हें "जिंकस" के नाम से जाना जाता है, ने 2011 में अपने पदार्पण के साथ शुरू हुए एक शानदार करियर के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। डोंबिवली (ठाणे), महाराष्ट्र में जन्मे बल्लेबाज ने बीसीसीआई, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए), अपने साथियों, परिवार और पत्नी राधिका को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देते हुए एक इंस्टाग्राम वीडियो के माध्यम से घोषणा साझा की। अपने शांत नेतृत्व, ठोस तकनीक और मैच जीतने वाले विदेशी टेस्ट प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध रहाणे ने टेस्ट में भारत की कप्तानी भी की। उन्होंने संकेत दिया कि वह कोचिंग, मेंटरिंग या कमेंट्री के माध्यम से क्रिकेट से जुड़े रहने की योजना बना रहे हैं।
- भारत ने ISSF वर्ल्ड कप 2026 में चार मेडल जीते – एक गोल्ड, एक सिल्वर और दो ब्रॉन्ज़ – जिससे इंटरनेशनल शूटिंग में उसकी बढ़ती ताकत का पता चलता है। आखिरी मेडल 10m एयर राइफल मिक्सड टीम इवेंट में आया, जहाँ सोनम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने 441.2 पॉइंट्स के साथ ब्रॉन्ज़ मेडल जीता। ईशा सिंह ने महिलाओं की 25m पिस्टल में गोल्ड जीता, संयम विज ने महिलाओं की 10m एयर पिस्टल में सिल्वर जीता, और मनु भाकर ने महिलाओं की 25m पिस्टल में ब्रॉन्ज़ मेडल जीता, जिससे राइफल और पिस्टल इवेंट्स में भारत का लगातार अच्छा प्रदर्शन दिखा।
- स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने एथलेटिक्स में एक गोल्ड और दो सिल्वर मेडल जीतकर अपनी मेडल टैली और मज़बूत कर ली। दिलीप महादू गावित ने पुरुषों की 100m T47 में 10.71 सेकंड के कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड टाइम के साथ गोल्ड जीता, जबकि मोहम्मद बासिल मोरसिंगनाकाथी ने 10.83 सेकंड में सिल्वर जीता, जिससे भारत इस इवेंट में पहली बार पहले-दूसरे स्थान पर रहा। मुरली श्रीशंकर ने पुरुषों की लॉन्ग जंप में 8.09 मीटर की छलांग लगाकर सिल्वर जीता, जो गोल्ड से 6 cm से चूक गए, और लगातार दूसरा कॉमनवेल्थ गेम्स सिल्वर मेडल जीता।

- भारतीय एथलीट तेजस्विन शंकर ने ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की डेकाथलॉन में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया और इस स्पर्धा में राष्ट्रमंडल पदक हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए। 27 वर्षीय ने क्रोनिक पटेला टेंडोनाइटिस से पीड़ित होने के बावजूद चुनौतीपूर्ण 10-इवेंट प्रतियोगिता में 7,976 अंक हासिल किए। वह पूरे आयोजन के दौरान शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में शामिल रहे और अंतिम 1,500 मीटर दौड़ में मजबूती से फिनिश करते हुए पोलियम स्थान हासिल किया। ग्रेनेडा के लिंडन विक्टर ने 8,096 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि कनाडा के डेमियन वार्नर ने 8,036 अंकों के साथ रजत पदक हासिल किया। 2022 के ऊंची कूद कांस्य पदक के बाद यह तेजस्विन का दूसरा राष्ट्रमंडल खेल पदक था।
- हर्ष सिंह 31 जुलाई 2026 को ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों के 60kg फ्राइनल में ऑस्ट्रेलिया के जोशुआ काटज़ को हराकर कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष जूडोका बने। 23 साल के एथलीट ने गेम्स में भारत के लिए पुरुषों का पहला जूडो गोल्ड मेडल पक्का करने के लिए मज़बूत टैक्टिकल स्किल्स और धैर्य दिखाया। इंटरनेशनल जूडो फ़ेडरेशन (IJF) द्वारा टॉप 100 जूडोका में शामिल, हर्ष ने ज़ाग्रेब ग्रैंड प्रिक्स और कज़ाकस्तान सहित बड़े इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में भारत को रिप्रेजेंट किया है। बैरीसी ग्रैंड स्लैम। उनकी यह कामयाबी उसी दिन आई जिस दिन अस्मिता डे ने गोल्ड मेडल जीता था, जो जूडो में भारत का अब तक का सबसे अच्छा कॉमनवेल्थ गेम्स परफॉर्मेंस था और इस खेल में देश की बढ़ती ताकत को दिखाता है।
- अस्मिता डे ने 31 जुलाई 2026 को ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की 48 किग्रा भार वर्ग के फाइनल में कनाडा की हेइडी कैच को हराकर जूडो में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनकर इतिहास रच दिया। 23 वर्षीय खिलाड़ी ने बेहतरीन सामरिक क्षमता और मानसिक शक्ति दिखाते हुए एक करीबी मुकाबले के बाद गोल्डन स्कोर प्रणाली के माध्यम से जीत हासिल की। वह कार्टर फाइनल में स्कॉटलैंड की ईवा इविंग और सेमीफाइनल में सारा एडलिंगटन को हराने के बाद फाइनल में पहुंची थीं। उनकी जीत ने राष्ट्रमंडल खेलों के जूडो में भारत के पांच रजत और छह कांस्य पदकों के पिछले सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड को समाप्त कर दिया। ऐतिहासिक जीत ने भारत को ग्लासगो खेलों में अपना पहला जूडो पदक भी दिलाया।
- कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की, जब नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की जेवलिन थ्रो स्पर्धा के फाइनल में सिल्वर मेडल जीता और यश वीर सिंह ने ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल किया, जिससे भारत ने इस इवेंट में पहली बार डबल पोलियम फिनिश किया। नीरज ने 85.83 मीटर का सीज़न-बेस्ट थ्रो किया, जबकि श्रीलंका के रुमेश पथिरगे ने 89.75 मीटर के गेम्स रिकॉर्ड थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता। यश वीर सिंह ने ब्रॉन्ज़ मेडल जीतने के अपने आखिरी प्रयास में 85.41 मीटर के पर्सनल-बेस्ट थ्रो के साथ करियर का बेस्ट प्रदर्शन किया। उनकी सफलता ने भारत

को 8वें दिन के अंत तक 23 मेडल तक पहुंचने में मदद की, जिसमें 5 गोल्ड, 12 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज़ मेडल शामिल हैं, जो एथलेटिक्स और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में भारत की बढ़ती ताकत को दिखाता है।

शिखर सम्मेलन

- केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 7-10 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में होने वाले 10वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IIMC) 2026 के लिए "स्केल विदाउट बाउंड्रीज़" थीम का अनावरण किया। दूरसंचार विभाग (DoT) और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) द्वारा आयोजित, एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्रौद्योगिकी मंच चार स्तंभों- सृष्टि, सुरक्षा, सशक्त और संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह कार्यक्रम 5G, 6G, AI, IoT, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, क्वांटम टेक्नोलॉजीज और ग्रीन टेक्नोलॉजीज का प्रदर्शन करेगा, जबकि भारत 6G अलायंस, PLI स्कीम और संचार साथी पोर्टल जैसी पहलों पर प्रकाश डाला जाएगा,

योजना समाचार

- हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की मछुआरा सम्मान निधि योजना उन जलाशय मछुआरों को आर्थिक मदद देती है जो सालाना मछली पकड़ने पर लगी रोक से प्रभावित होते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस योजना की घोषणा की है। यह योजना योग्य मछुआरों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सिस्टम के ज़रिए हर साल ₹3,500 देती है। लगभग 3,700 मछली पकड़ने वाले परिवारों को इसका फ़ायदा मिलने की उम्मीद है, जिसके लिए हर साल लगभग ₹1.20 करोड़ दिए जाएंगे। योग्य लाभार्थियों को लाइसेंस वाले जलाशय मछुआरे, रजिस्टर्ड फिशरीज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्य और NFDP रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। यह योजना गोबिंद सागर, पोंग डैम, कोल डैम, चमेरा और रंजीत सागर जलाशयों को कवर करती है, साथ ही रोज़ी-रोटी की सुरक्षा और टिकाऊ मछली पालन संरक्षण को बढ़ावा देती है।
- महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना (MJPJAY) महाराष्ट्र सरकार की एक खास हेल्थ इश्योरेंस स्कीम है, जिसे 2012 में स्टेट हेल्थ एश्योरेंस सोसाइटी ने शुरू किया था। पहले इसे राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना के नाम से जाना जाता था। इसमें हर परिवार को सालाना ₹1.5 लाख का कैशलेस इलाज मिलता है, जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए ₹2.5 लाख तक का कवरेज मिलता है। आयुष्मान भारत PM-JAY के तहत आने वाले परिवार भी ₹5 लाख का कंबाईंड हेल्थ कवरेज ले सकते हैं। यह स्कीम कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, न्यूरोलॉजी, क्रिटिकल केयर और बड़ी सर्जरी समेत 34 स्पेशलिटी में 996 मेडिकल प्रोसीजर में इलाज देती है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सस्ती हेल्थकेयर मिलती है।

- महाराष्ट्र सरकार ने 1 अगस्त 2017 को माझी कन्या भाग्यश्री योजना शुरू की थी। इसका मकसद लड़कियों की सामाजिक, पढ़ाई-लिखाई और पैसे की हालत को बेहतर बनाना है। महिला और बाल विकास विभाग इसे लागू करता है। इस योजना का मकसद भ्रूण हत्या को रोकना, लड़कियों की पढ़ाई को बढ़ावा देना, परिवार नियोजन को बढ़ावा देना और बच्चों के लिंग अनुपात को बेहतर बनाना है। जिन परिवारों में एक बेटी है, उन्हें ₹50,000 का फिक्स्ड डिपॉजिट मिलता है, जबकि जिन परिवारों में दो बेटियां हैं, उन्हें हर बच्चे के लिए ₹25,000 मिलते हैं। लड़की के 18 साल का होने पर डिपॉजिट मैच्योर हो जाता है। जिन परिवारों की सालाना कमाई ₹7.5 लाख से कम है, वे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
- दिल्ली सरकार ने फाइनेंशियल मदद देने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। इस स्कीम के तहत, योग्य महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए हर महीने ₹2,500 मिलेंगे। सरकार ने दिल्ली बजट 2026-27 में इसे लागू करने के लिए ₹5,110 करोड़ दिए हैं। इस स्कीम से 17 लाख से ज़्यादा महिलाओं को फ़ायदा होने की उम्मीद है। एलिजिबिलिटी में दिल्ली में रहना, उम्र 21-60 साल के बीच और परिवार की सालाना इनकम ₹2.5 लाख तक शामिल है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल 1 अगस्त 2026 से शुरू होगा। यह स्कीम आर्थिक सुरक्षा, शिक्षा, हेल्थकेयर, स्किल डेवलपमेंट और फाइनेंशियल इनक्लूजन पर फोकस करती है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार

- भारत ने घोषणा की है कि भविष्य के स्पेस लॉन्च व्हीकल में देश में बने सेमीकंडक्टर चिप्स लगे होंगे, जो टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्काईरूट एयरोस्पेस के विक्रम-1 के सफल ऑर्बिटल टेस्ट फ़्लाइट के बाद इस पहल की घोषणा की, जिससे भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर की तेज़ ग्रोथ पर रोशनी पड़ी। ये स्पेस-ग्रेड सेमीकंडक्टर नेविगेशन, फ़्लाइट कंट्रोल, टेलीमेट्री, ऑनबोर्ड कंप्यूटर और कम्युनिकेशन जैसे ज़रूरी सिस्टम को पावर देते हैं, और बहुत ज़्यादा रेडिएशन, वाइब्रेशन और तापमान में बदलाव को भी झेलते हैं। यह कदम सप्लाई-चेन सिक्योरिटी को मज़बूत करता है, इम्पोर्ट पर निर्भरता को कम करता है, और चार साल के अंदर देश में बने प्रोसेसर और मिशन इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के ISRO के प्लान को सपोर्ट करता है।
- भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) के वैज्ञानिकों ने मकड़ी की दो नई प्रजातियों की खोज की है - मेघालय से सिमोनिया लॉबाह और हमातलिवा आंध्र प्रदेश से पापिकोंडा - भारत की डॉक्यूमेंटेड बायोडायवर्सिटी को बढ़ा रहा है। ये खोजें साइंटिफिक जर्नल जूटाक्सा और रिकॉर्ड्स ऑफ़ द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया में पब्लिश हुईं। सिमोनिया लॉबाह, क्रेम के अंदर खोजा गया। लॉबाह गुफा, सिमोनिया जीनस की भारत की पहली दर्ज प्रजाति

है और यह गुफा में रहने वाली रे स्पाइडर है। हमातलिवा पापिकोंडा, पापिकोंडा नेशनल पार्क में पाई जाने वाली एक एक्टिव शिकार करने वाली लिंक्स मकड़ी है। ये नतीजे भारत में टैक्सोनॉमी, वाइल्डलाइफ सर्वे और बायोडायवर्सिटी कंज़र्वेशन के महत्व को दिखाते हैं।

- जूलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (ZSI) ने 12 साल की रिसर्च के बाद, तितलियों और पतंगों की 13,703 प्रजातियों को डॉक्यूमेंट करते हुए, देश की पहली बड़ी लेपिडोप्टेरा इन्वेंट्री पूरी की। डॉ. नवनीत सिंह और डॉ. राहुल जोशी के नेतृत्व में, इस प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर फ़ील्ड सर्वे, म्यूज़ियम कलेक्शन, सैपल वेरिफ़िकेशन और लिटरेचर रिव्यू शामिल थे, जिसके नतीजे में जूटाक्सा में 22-वॉल्यूम का कैटलॉग पब्लिश हुआ। इन्वेंट्री में 3,705 जेनेरा, 102 फ़ैमिली, 240 सबफ़ैमिली और 31 सुपरफ़ैमिली रिकॉर्ड हैं, जबकि भारत को 2,205 प्रजातियों के साथ जियोमेट्रोइडिया पतंगे की डाइवर्सिटी के लिए ग्लोबल हॉटस्पॉट के तौर पर पहचाना गया है, जो टैक्सोनॉमी, बायोडायवर्सिटी कंज़र्वेशन और क्लाइमेट रिसर्च में काफ़ी मदद करता है।
- आईबीएम और भारतीय एआई स्टार्टअप सर्वम ने भारत की सरकारों और विनियमित क्षेत्रों के लिए सॉवरैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) समाधानों के विकास में तेजी लाने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। सहयोग का उद्देश्य बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक प्रशासन और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे सहित क्षेत्रों के लिए सुरक्षित, बहुभाषी और शासन केंद्रित एआई सिस्टम बनाना है। आईबीएम डेटा सुरक्षा, एआई शासन, अनुपालन और बुनियादी ढांचे के नियंत्रण का समर्थन करने के लिए अपना सॉवरैन कोर प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा, जबकि सर्वम बहुभाषी भाषा मॉडल, वॉयस एआई और स्थानीय रूप से विकसित तर्क मॉडल जैसी भारत-विशिष्ट तकनीकों का योगदान देगा। यह पहल डेटा, मॉडल और संचालन पर नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए संगठनों को एआई प्रयोग से बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन में स्थानांतरित करने पर केंद्रित है।
- स्पूडोलागुविया नाम की एक नई मीठे पानी की हिलस्ट्रीम कैटफ़िश प्रजाति की खोज की खैरी ओडिशा के मयूरभंज जिले के बुधबलंगा नदी में पाई जाती है। इस खोज को आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिका जूटाक्सा में 26 जुलाई 2026 को प्रकाशित किया गया था, जो भारत के मीठे पानी की जैव विविधता के रिकॉर्ड में शामिल हो गया। प्रजाति स्पूडोलागुविया जीनस से संबंधित है, जो आमतौर पर दक्षिण एशिया की तेज बहने वाली नदियों में पाई जाती है और स्वस्थ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संकेतक के रूप में कार्य करती है। शोधकर्ताओं ने इस प्रजाति की पहचान इसकी अनूठी शारीरिक विशेषताओं के माध्यम से की, जिसमें इसके पृष्ठीय पंख के आधार पर एक विशिष्ट मांसल उभार शामिल है। इस प्रजाति का नाम खैरी के नाम पर रखा गया, जो प्रसिद्ध अनाथ रॉयल बंगाल बाघिन थी, जो संरक्षणवादी सरोज राज चौधरी से जुड़ी थी, जो ओडिशा की वन्यजीव संरक्षण विरासत पर प्रकाश डालती है।

महत्वपूर्ण दिन

- **CRPF स्थापना दिवस** हर साल 27 जुलाई को भारत के सबसे बड़े सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPF) सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फोर्स (CRPF) की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2026 में, फोर्स ने अपना 87वां स्थापना दिवस मनाया, जिसमें आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी, लेफ्ट-विंग एक्सट्रीमिज़्म (LWE) ऑपरेशन, चुनाव सुरक्षा, VIP सुरक्षा और आपदा राहत में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता दी गई। मूल रूप से 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में स्थापित, CRPF एक्ट, 1949 के लागू होने के बाद इसका नाम बदलकर CRPF कर दिया गया। फोर्स को 1959 के हॉट स्पिंग्स बलिदान के लिए भी याद किया जाता है, जहाँ 10 कर्मियों ने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी थी। आज, 246 से ज़्यादा बटालियन और CoBRA (कमांडो बटालियन फॉर रेज़ोल्यूट एक्शन) और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) जैसी स्पेशल यूनिट्स के साथ, CRPF नेशनल सिक््योरिटी बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रहा है और यूनाइटेड नेशंस पीसकीपिंग मिशन में भी अहम योगदान दिया है।
- **कारगिल विजय दिवस** हर साल 26 जुलाई को 1999 के कारगिल युद्ध में भारत की जीत के उपलक्ष्य में और भारतीय सशस्त्र बलों के साहस और बलिदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। 2026 में, राष्ट्र ने भारतीय वायु सेना के ऑपरेशन सफेद सागर द्वारा समर्थित ऑपरेशन विजय के माध्यम से हासिल की गई इस ऐतिहासिक जीत की 27वीं वर्षगांठ को चिह्नित किया। संघर्ष मई 1999 में शुरू हुआ, जब पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों ने लद्दाख के कारगिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के साथ रणनीतिक पदों पर कब्जा कर लिया। टोलोलिंग और टाइगर हिल पर सफल कब्जा करने सहित गहन लड़ाई के बाद, भारतीय सेना ने कब्जे वाली चोटियों पर नियंत्रण हासिल कर लिया। यह दिन कैप्टन विक्रम बत्रा (पीवीसी), लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे (पीवीसी), और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव (पीवीसी) जैसे बहादुर सैनिकों को भी श्रद्धांजलि देता है, जिनकी असाधारण वीरता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है और देशभक्ति, बलिदान और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है।
- **वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे** हर साल 28 जुलाई को वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है, जो दुनिया भर में लिवर की बीमारी और रोकी जा सकने वाली मौतों का एक बड़ा कारण है। 2026 की थीम, "हेपेटाइटिस: लेट्स ब्रेक इट डाउन," टेस्टिंग, वैक्सीनेशन, इलाज और अच्छी हेल्थकेयर में आने वाली रुकावटों को दूर करने पर फोकस करती है, साथ ही स्टिग्मा को कम करती है और हेल्थ इकिटी में सुधार करती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन (WHO) के नेतृत्व में, यह कैम्पेन 2030

तक वायरल हेपेटाइटिस को एक पब्लिक हेल्थ खतरे के रूप में खत्म करने के ग्लोबल लक्ष्य का समर्थन करता है और जल्दी डायग्नोसिस, सुरक्षित हेल्थकेयर प्रैक्टिस और बड़े पैमाने पर पब्लिक अवेयरनेस पर ज़ोर देता है।

- **वर्ल्ड नेचर कंज़र्वेशन डे** हर साल 28 जुलाई को नेचुरल रिसोर्स, बायोडायवर्सिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बचाव पर ज़ोर देने के लिए मनाया जाता है। 2026 में मनाया जाने वाला यह दिन क्लाइमेट चेंज, प्रदूषण, जंगलों की कटाई और हैबिटेट के नुकसान से खतरे में पड़े जंगलों, वाइल्डलाइफ़, पानी के रिसोर्स, मिट्टी और इकोसिस्टम को बचाने की ज़रूरत पर ज़ोर देता है। 1972 के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस और कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क जैसी ग्लोबल पहलों से प्रेरित होकर, यह दिन सरकारों और नागरिकों को इको-फ्रेंडली तरीके अपनाने के लिए बढ़ावा देता है, यह मानते हुए कि हेल्दी इकोसिस्टम फूड सिक््योरिटी, साफ़ पानी, क्लाइमेट स्टेबिलिटी और लंबे समय के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं।
- **ह्यूमन ट्रेफिकिंग** के बारे में जागरूकता बढ़ाने, पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा करने और इस अपराध के खिलाफ ग्लोबल एक्शन को मज़बूत करने के लिए हर साल 30 जुलाई को वर्ल्ड डे अगेस्ट ट्रेफिकिंग इन पर्सन्स मनाया जाता है। 2013 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली (UNGA) द्वारा घोषित, 2026 की थीम, "ट्रेड बिहाइंड द स्कैम," नकली विदेशी जॉब ऑफ़र के ज़रिए ट्रेफिकिंग पर ज़ोर देती है जो पीड़ितों को साइबर-इनेबल्ड फाइनेंशियल स्कैम में धकेलती है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम (UNODC) के नेतृत्व में, ग्लोबल कोशिशें पीड़ितों की सुरक्षा, क्रॉस-बॉर्डर सहयोग, एंटी-ट्रेफिकिंग जांच और अपराधियों पर मुकदमा चलाने पर फोकस करती हैं, साथ ही ऑर्गनाइज़्ड क्राइम, साइबर क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग और ह्यूमन ट्रेफिकिंग के बीच संबंधों को भी सुलझाती हैं।
- **इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे** हर साल 30 जुलाई को लोगों, समुदायों और देशों के बीच शांति, आपसी समझ और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 2011 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली (UNGA) द्वारा घोषित यह दिन अलग-अलग संस्कृतियों के बीच बातचीत, विविधता के लिए सम्मान और दुनिया भर में सहयोग को बढ़ावा देता है। UNESCO की कल्चर ऑफ़ पीस पहल से प्रेरित होकर, यह दोस्ती को बढ़ावा देने और सहानुभूति और समझ के ज़रिए झगड़ों को सुलझाने में युवाओं की भूमिका पर ज़ोर देता है। इस दिन को कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, शांति बातचीत, कम्युनिटी एक्टिविटी और जागरूकता कैम्पेन के ज़रिए मनाया जाता है, जो दोस्ती को एक ज़्यादा सबको साथ लेकर चलने वाली और शांतिपूर्ण दुनिया की नींव के तौर पर मज़बूत करता है।

वीकली वन लाइनर्स 27 जुलाई से 1 अगस्त, 2026

- फेफड़ों के कैंसर की रोकथाम, शीघ्र पता लगाने, निदान और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 1 अगस्त 2026 को विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस 2026 मनाया गया। 2026 का विषय, "फेफड़ों के कैंसर के माध्यम से एक साथ", रोगियों, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों, शोधकर्ताओं और समुदायों के बीच सहयोग पर केंद्रित है ताकि करुणा और समर्थन के साथ बीमारी से लड़ा जा सके। यह अवलोकन स्क्रीनिंग कार्यक्रमों, चिकित्सा अनुसंधान, स्वस्थ जीवन शैली और फेफड़ों के कैंसर से जुड़े कलंक को कम करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह दिन पहली बार 2012 में फोरम ऑफ इंटरनेशनल रेस्पिरेटरी सोसाइटीज (FIRS), इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ लंग कैंसर (IASLC) और CHEST सहित संगठनों के प्रयासों से मनाया गया था। चूंकि फेफड़ों का कैंसर दुनिया भर में कैंसर से संबंधित मौतों के प्रमुख कारणों में से एक है, इसलिए अभियान रोगियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा पहुंच, नवीन उपचार और बेहतर अस्तित्व के परिणामों को बढ़ावा देता है।
- 1989 में सर टिम बर्नर्स-ली द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब (www) के आविष्कार के उपलक्ष्य में 1 अगस्त 2026 को वर्ल्ड वाइड वेब दिवस 2026 मनाया गया। CERN में विकसित, वेब ने सूचना, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बैंकिंग, मनोरंजन और डिजिटल सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करके वैश्विक संचार को बदल दिया। आधुनिक इंटरनेट अनुभव की नींव HTML (हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज), HTTP (हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल) और URL (यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर) जैसी तकनीकों पर बनी थी। समय के साथ, वेब सरल स्थिर पृष्ठों से इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म और उन्नत AI-संचालित डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में विकसित हुआ। यह दिन डिजिटल समावेशन, साइबर सुरक्षा, जिम्मेदार इंटरनेट उपयोग और तकनीकी नवाचार के महत्व पर जोर देता है।

शोक समाचार

- वरिष्ठ कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट का 26 जुलाई 2026 को देहरादून में 85 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। डोईवाला और राजपुर से तीन बार MLA

रहे, उन्होंने ND तिवारी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर काम किया, ट्रांसपोर्ट, लेबर और टेक्निकल एजुकेशन जैसे डिपार्टमेंट संभाले। पॉलिटिक्स के अलावा, उन्होंने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के फाउंडर मेंबर के तौर पर स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में अहम योगदान दिया, रायपुर क्रिकेट स्टेडियम के डेवलपमेंट में मदद की, और INTUC में अपनी लीडरशिप के ज़रिए लेबर वेलफेयर के लिए काम किया।

- पूर्व थल सेनाध्यक्ष (COAS) जनरल विश्व नाथ (VN) शर्मा का 31 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में 95 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने चार दशकों से ज़्यादा के शानदार मिलिट्री करियर को खत्म किया। उन्होंने 1 मई 1988 से 30 जून 1990 तक 14वें आर्मी चीफ के तौर पर काम किया और आज़ादी के बाद आर्मी के सबसे ऊंचे पद पर पहुंचने वाले पहले कमीशनड ऑफिसर बने। 1950 में 16वीं लाइट कैवेलरी में कमीशनड होने के बाद, उन्होंने 1987 में चीन के साथ सुमदोरोंग चू स्टैंड-ऑफ के दौरान अहम भूमिका निभाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ ने भारत की रक्षा तैयारियों में उनकी शानदार सेवा और योगदान के लिए उन्हें श्रद्धांजलि दी।
- इटली के मशहूर फुटबॉलर फ्रैंको बारेसी का 66 साल की उम्र में निधन हो गया। AC मिलान ने पहले झूठी अफवाहों को खारिज करने के बाद 31 जुलाई 2026 को इस खबर की पुष्टि की। फुटबॉल इतिहास के सबसे महान डिफेंडरों में से एक माने जाने वाले बारेसी ने अपना पूरा 20 साल का प्रोफेशनल करियर AC मिलान के साथ बिताया, जिसमें उन्होंने 700 से ज़्यादा मैच खेले, 15 सीज़न तक क्लब की कप्तानी की और छह Serie A टाइटल और तीन यूरोपियन कप जीते। उन्होंने इटली के साथ 1982 का FIFA वर्ल्ड कप भी जीता और घुटने की सर्जरी से ठीक होने के बावजूद 1994 के FIFA वर्ल्ड कप फाइनल में नेशनल टीम की कप्तानी की। उनकी लीडरशिप, डिफेंसिव बेहतरीन और वफ़ादारी ने वर्ल्ड फुटबॉल में एक हमेशा रहने वाली विरासत छोड़ी।

स्टेटिक टेकअवे

पहलू	विवरण
उत्तराखंड	CM: पुष्कर धामी, गवर्नर: गुरमीत सिंह, राजधानी: देहरादून (विंटर)
राजस्थान	CM: भजनलाल शर्मा, गवर्नर: हरिभाऊ बागड़े, राजधानी: जयपुर
गुजरात	CM: भूपेंद्र पटेल, गवर्नर: आचार्य देवव्रत, राजधानी: गांधीनगर
आंध्र प्रदेश	CM: चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर: अब्दुर नज़ीर, राजधानी: अमरावती
असम	CM: हेमंत सरमा, गवर्नर: लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, राजधानी: ईटानगर
महाराष्ट्र	CM: देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर: जिष्णु देव वर्मा, राजधानी: मुंबई
छत्तीसगढ़	CM: मोहन मांझी, गवर्नर: रामेन डेका, राजधानी: रायपुर
तमिलनाडु	CM: जोसेफ विजय, गवर्नर: आर आर्लेकर, राजधानी: चेन्नई
यूएसए	राष्ट्रपति: डोनाल्ड ट्रम्प

वीकली वन लाइनर्स 27 जुलाई से 1 अगस्त, 2026

पहलू	विवरण
वेनेजुएला	अध्यक्ष: डेल्सी रोड्रिगेज
नेपाल	प्रधानमंत्री: बालेन शाह
भारतीय रिजर्व बैंक	राज्यपाल: संजय मल्होत्रा
डीबीएस बैंक	सीएमडी और एमडी: रजत वर्मा

